

25 सितम्बर के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं के संबंधों में आई तल्खी बरकरार

समन्वय समिति की बैठक में गहलोत और पायलट की ना नज़रें मिलीं ना हुआ अभिवादन



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर, 23 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है। गत 23 नवंबर को जयपुर में हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में हुई बैठक के दौरान भी संबंधों की तल्खी स्पष्ट रूप से नजर आई। कांग्रेस की कोर्दिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक

गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों मौजूद तो रहे, लेकिन दोनों नेताओं में ना तो अभिवादन का आदान-प्रदान हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई।

हुआ यू कि इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुंचे।

बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे

- हुआ यू कि, इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुंचे।
- बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे वैसे ही, पायलट के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए।
- गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए। इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा पर दोनों की नज़रें नहीं मिलीं।

ही गहलोत कक्ष में पहुंचे तभी पायलट



सचिन पायलट

के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ जोड़कर गहलोत का अभिवादन किया। गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए।

इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा, पर दोनों की नज़रें नहीं मिलीं। बैठक गहलोत के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन पायलट आधे घंटे के बाद

ही चले गए।

समन्वय समिति की इस बैठक में तय किया गया है कि समन्वय समिति के सदस्य 25 नवंबर को झालावाड़ से अलवर तक के पूरे यात्रा मार्ग का जायजा लेंगे और किस तरह से यात्रा को संपन्न कराया जाए इस बारे में रणनीति तय की जाएगी। बुधवार को हुई बैठक में समिति के सभी 32 सदस्य मौजूद थे।

ई.डब्ल्यू.एस. पर कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की चुनौती

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। कांग्रेस नेता जया ठाकुर, जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव हैं, ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के 7 नवम्बर के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये याचिका दायर कर दी, जिस फैसले में न्यायालय ने नौकरियों तथा प्रवेशों में इकोनॉमिकली वीकर सैकशंस (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये 2019 में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले का अनुमोदन कर दिया गया था।

- कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की नेता जया ठाकुर ने गरीबों को आरक्षण संबंधी फैसले को पलटने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

ज्ञातव्य है कि इस आरक्षण में एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. श्रेणियों के गरीब लोगों को शामिल नहीं किया था।

उन्होंने पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के अल्पमत के फैसले का समर्थन करते हुये, तीन जजों के बहुमत वाले फैसले को उलटने की माँग की।

इस ऐतिहासिक महत्व के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की खंडपीठ ने कहा था कि आर्थिक न्याय प्रदान करने के सरकार के प्रयास को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र का एम.वी.ए. मॉडल, बिहार में लाना चाहती है जे.डी.यू.

एम.वी.ए. (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) गठबंधन, जिसमें शिव सेना, पवार की पार्टी व कांग्रेस भी शामिल हैं, काफी हद तक सफल रहा और महाराष्ट्र में तथा सरकार भी बनाई थी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। महाराष्ट्र के एम.वी.ए. मॉडल को बिहार तथा उत्तर

सेना (यू.बी.टी.) नेता आदित्य ठाकरे तथा पार्टी संसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पटना में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भेंट की तथा उसके बाद उनकी

- आदित्य ठाकरे व प्रियंका चतुर्वेदी, पटना में उप मु.मंत्री नीतीश कुमार से इस संदर्भ में मिले।
- नीतीश का नारा है कि, अगर गैर भाजपा पार्टियाँ संगठित होकर चुनाव लड़ें तो, भाजपा को पराजित किया जा सकता है।
- हालांकि, शिव सेना से हाथ मिलाने से नीतीश का मौलिक राजनीतिक सोच आहत होता है, पर इस दुविधा से यह कहकर निपटा जा रहा है कि, गठबंधन भाजपा को हराने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

प्रदेश तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।

इस प्रकार के प्रयास के संकेत बुधवार को उस समय मिले, जब शिव

मोर्तिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। शिव सेना पिछले कुछ वर्षों से बिहार में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही है लेकिन उसे कोई खास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘फुटबॉल फैडरेशन, फुटबॉल के अलावा सब कुछ करती है’

अपनी इस तीखी टिप्पणी की अनुपालना करते हुए सुप्रीम कोर्ट 6 दिसम्बर के नये संविधान के बारे में सुनवाई करेगा

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ऑल इण्डिया फुटबॉल फैडरेशन (ए.आई.एफ.एफ.) और इस खेल इकाई से संबंधित संविधान के मसौदे पर उठी आपत्तियों को लेकर दायर एक याचिका पर 6 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक बैंच ने गौर किया कि खेल इकाई को कुछ त्वरित मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, बैंच ने टिप्पणी की थी कि फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसने लोगों से कहा था कि वे स्पोर्ट्स नेशनल फैडरेशन के संविधान मसौदे पर न्याय मित्र को सुझाव दें। बैंच ने टिप्पणी की

- सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को जल्द से जल्द कराने की दृष्टि से अपने पुराने निर्णय को भी बदला, जिसके तहत तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी, फुटबॉल फैडरेशन का कामकाज देखने के लिये।

थी “हम फुटबॉल के अलावा सबकुछ कर रहे हैं।

बैंच ने गत 9 नवम्बर को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन से पूछा था कि आपत्तियों को सारणीबद्ध करने के लिए न्याय मित्र के रूप में बैंच की सहायता कौन कर रहा है ताकि संविधान मसौदे को अंतिम रूप दिया जा

सके।

इससे पहले टॉप कोर्ट ने इसके द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी भंग कर दी, जिनका गठन नेशनल फुटबॉल फैडरेशन के गठन के लिए किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर निलम्बन का खंडन करने की सुविधा प्रदान की। यह निलम्बन अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉल फैडरेशन, फीफा, ने लगाया था। इससे भारत को अण्डर-17 वीमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन की सुविधा भी मिली।

18 मई को इसने रिटायर्ड जस्टिस अमिल आर. दवे के नेतृत्व में प्रबंध समिति गठित की जिसने पूर्व सी.ई.सी. एस.वाय. कुरैशी, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली और राजनेता प्रफुल्ल पटेल शामिल थे।

यह आदेश युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। विद्युत-शुल्क तय करने में तदर्थवाद का उल्लेख करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों के नियामक आयोगों (रेग्युलेटरी कमीशंस) को निर्देश दिये हैं कि वे तीन माह के अन्दर, शुल्क के निर्धारण की शर्तों पर अधिनियम की

- सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर कम्पनी की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों को उक्त निर्देश दिए।

धारा 181 के तहत विनिमय तैयार करें। यह फैसला महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन के खिलाफ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन द्वारा दायर की गई अपील को खरिज करते हुये दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नियामक आयोगों ने अधिनियम में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, आयोग में अधिकतर रिटायर्ड सरकारी अफसर नियुक्त होते हैं। सरकार इन अफसरों की जन्मतिथि से पूरी तरह वाकिफ होती है। अतः चीफ आयुक्त इस तरह नियुक्त किया जाता है कि, उसको काम करने का समय दो-ढाई साल ही मिले

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एवं अपेक्षित मान्यता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक ढाँचे या लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध राष्ट्र के संचालन के लिये दो महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें हैं, लेकिन क्या ये दोनों हमारे देश में मौजूद हैं?

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ इस समय इसी प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि चार जनहित याचिकाओं के समूह ने माँग की है कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सुधार की विफारिश/अनुशंसाएं की जायें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह केन्द्र की इस स्थिति पर प्रश्न खड़े किये कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिये कोई भी कानून नहीं है। अदालत ने इस प्रकार के कानून

- संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में चुप हैं। इस चुप्पी का लाभ लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त जल्दी-जल्दी बदल दिए जाते हैं, जिनको काम करने का लम्बा समय नहीं मिलता।

- यू.पी.ए. सरकार के दस साल के शासन में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। एन.डी.ए. सरकार के आठ साल में आठ नये-नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई।
- संविधान की इस चुप्पी का मतलब था, सरकार संसद में इसके मुतल्लिक कानून पारित करे। पर गत 72 सालों में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि, प्रजातंत्रीय व्यवस्था के सुचारु रूप से काम करने के लिये, निष्पक्ष व जायज़ चुनाव होना जरूरी है, पर, क्या यह अपने देश में हो रहा है?

के अभाव को “व्याकुलता पैदा करने वाली प्रवृति या स्थिति” की संज्ञा दी है। आज सुनवाई जारी रखते हुये, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के

चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियाँ एवं प्रश्न आये। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कुछ विशिष्ट फाइलों की माँग की- आयोग में

19 नम्बर को हुई अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल। सुनवाई कल जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की इस संविधान पीठ ने कहा कि बैंच यह जानना चाहती है कि क्या नियुक्ति में कोई “चालबाजी” हुई थी क्योंकि उन्हें अभी हाल ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी तथा तुरन्त ही उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त कर दिया गया था।

इस याचिका-समूह की सुनवाई के दौरान, ऐक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण ने अरुण गोयल की नियुक्ति की ही प्रक्रिया का उल्लेख किया। भूषण ने जोर देकर कहा कि गोयल, जो अभी-अभी सेवानिवृत्त हुये आई.ए.एस. अधिकारी हैं, को तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग का हिस्सा बना दिया गया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चन्द्र पान्डे की नियुक्ति हुई थी। गत सप्ताह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में कितने पद हैं?’

जोधपुर, 23 नवम्बर (कास)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में हलफनामा और तालिका पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में सभी श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और निश्चित रूप से यह भी

- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने राज्य सरकार से हलफनामा पेश कर जानकारी देने को कहा।

बताएं कि इन पदों की संख्या कितनी है और रिक्त पदों को सरकार कब तक भर देगी। जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता रणजीत जोशी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की बात पर पायलट कैम्प के निशाने पर विजय बैसला

पायलट ने कहा, यात्रा से भाजपा के लोग विचलित हैं, वे यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं

- इंद्राज गुर्जर ने कहा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समाज में बहुत सम्मान है, लेकिन विजय बैसला...।
- इंद्राज गुर्जर ने कहा कि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया।
- राजेन्द्र गुद्धा बोले, यह सचिन पायलट और गुर्जर समाज को बदनाम करने का प्रयास है, अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है।

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान और गुर्जर समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी मेहमान का विरोध किया जाए। राजस्थान में तो मेहमान नवाजी की परंपरा है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समाज में बहुत सम्मान है लेकिन विजय बैसला तथाकथित गुर्जर नेता है।

विजय बैसला किसी की राजनीतिक साजिश का शिकार हैं और समाज के लोगों ने ही अब उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की आरक्षण संघर्ष समिति और समाज के 72 युवाओं के बलिदान से समाज को आरक्षण मिला है। अगर गुर्जर आरक्षण में कोई विरसंगतियां है तो विजय बैसला को समाज के विधायकों को साथ सरकार से

वार्ता करनी चाहिए, लेकिन विजय बैसला बंद कमरे में वार्ता करके चले आते हैं।

इंद्राज गुर्जर ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया कि विजय बैसला किन लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। उन लोगों को समाज के विरोध के सामने भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि विजय बैसला पिछले 2 दिन से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वह भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्हें भाजपा की बात करनी चाहिए।

इसी मामले को लेकर मंत्री राजेंद्र गुद्धा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पार्टी लिए उनके विरोधी नेता नए-नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विजय बैसला को भी सामने रहे हैं। यह सब सचिन पायलट और गुर्जर

समाज को बदनाम करने की साजिश है। गुद्धा ने कहा कि अगर विजय बैसला के साथ सरकार ने कोई समझौता किया था तो उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय का घेराव करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का क्या तुक है। राहुल गांधी कोई सरकार में नहीं है। विजय बैसला की समस्याओं का समाधान तो केवल मुख्यमंत्री के पास है। राजेंद्र गुद्धा ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चन्द्र पान्डे की नियुक्ति हुई थी। गत सप्ताह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को ज़िंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीक़े से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

—संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लोकतंत्र की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय उसका अधिकार है। विवाद प्रत्येक स्तर पर होते रहते हैं और होते रहेंगे। व्यक्ति अकेला नहीं जीता, समूह में जीता है। विवाह की एक संस्था के कारण एक से दो होते हैं और फिर परिवार बनता है। इस समूह का विस्तार होकर वह समूचे विश्व व समूचे ब्रह्मांड तक पहुँचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निर्जीव जगत से भी मानव को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिटाने हेतु उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समायोजन न होने पर प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है और उसके कारण हो रही प्राकृतिक आपदायें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व स्तरीय संस्थाएँ भी बनानी पड़ी हैं। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाद हेतु मानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्हीं विवादों को निपटाने हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाएँ हैं जिन्हें हम क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा देते हैं। पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक ढांचा है। विधायिका के अन्तर्गत राज्य में विधानसभाएँ व केन्द्रीय स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत से लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वायत्त शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका व विकास प्रत्यास अथवा विकास ऑथोरिटी आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निर्वाचन से बनती हैं वे विधायिका की तरह काम करती हैं और जहाँ निर्वाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों का नीचे के स्तर पर जो अन्तर्संबंध है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इनमें अन्तर्संबंध न होने पर किसी भी एक के निरंकुश होने की संभावना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मृत्युदंड के निर्णय पर भी राष्ट्रपति निर्णय देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में की जाती है। संसद के निर्णय की संवैधानिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संपूर्ण भूमिका इसलिये है कि सभी स्तरों का निर्णय तथा उनकी अपील व समीक्षा हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती हैं। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निर्वाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर निर्णय दिया जाता है वह व्यक्ति व समूह उस स्तर पर पंच-सरपंच का कार्य कर रहा है। निर्णयकर्ता जो भी पंच-सरपंच हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्गत न्याय करें। विधायिका में भ्रष्ट लोग आ जाते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत निर्णय देते हैं, दलीय आधार पर निर्णय करते हैं। प्रशासनिक तंत्र भी भोरे भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और निष्पक्ष नहीं रह पाता। अन्ततोगत्वा न्यायपालिका ही आशा की किरण बनती है। इस दृष्टि से हाल ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा ज़ोरों पर है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री की लिखे एक पत्र का उल्लेख है। इस तथाकथित पत्र

में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने हेतु सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिखे पत्र के मुख्य बिंदुओं का भी उल्लेख है। ये समाचार सत्य है कि नहीं परन्तु तथाकथित प्रच्युतर के बिंदु सभी के लिये विचारणीय हैं विशेष रूप से न्यायपालिका के लिये। सोशल मीडिया की चर्चा में संपूर्ण न्यायपालिका एवं मुख्यरूप से उच्चतम न्यायालय पर ये बिंदु लागू होते हैं। सामान्यतः 2 से 3 बजे तक सामान्यतः पीठासीन अधिकारी लंच रखते हैं और 4 बजे कार्य बंद हो जाता है। अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह 9 से 6 तक कार्य क्यों नहीं हो पाता और क्या उसे लागू नहीं किया जा सकता? उल्लेखनीय

है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फौजदारी मामलों के दिये जाते हैं और लम्बे-लम्बे निर्णय लिखाने भी पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की छुट्टियों को भी काम किया जा सकता है। निश्चय ही जनहित में यह निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार-रविवार का अवकाश अंग्रेजों के समय का तरीका रहा है और यह प्रयोग भारत के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सफल नहीं रहा है। लोगों में पुरानी 10 से 5 की आदत पड़ी हुई है। न्यायालय में गर्मी को छुट्टियों की निश्चय ही कोई तुक नहीं है। न्याय तो 3६5 दिन व 24 घंटे करना होता है। राजधर्म में राजा को न्याय हेतु सर्वेव उपलब्ध रहना होता है। अपराध करने वाले तो छुट्टियों का नाजायज लाभ उठाते हैं और इन दिनों कई अपराध बढ़ते हैं। कई बार रात्रि में भी सुनवाई की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु सीमा अधिक है और राज्यकोष से सभी सुविधाएँ यथा कार, बंगला, सुरक्षा, भरपूर वेतन तथा केबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिश्रम की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। रविवार की ओर आवश्यक अवकाशों के अलावा 3०0 दिन कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री 3६5 दिन काम करते हैं और न्यायपालिका का अंग्रेजों जैसा पेटर्न बदलना चाहिये। वकील, सरकार व जज बैठ कर हमारी न्याय संहिताओं को अधिक व्यावहारिक बनायें तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट तक साधारण, सामान्य निर्धन व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता वह अत्यधिक व्यय-साध्य है, इस पर भी विचार होना चाहिये।

न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें अन्य कई कारण भी हैं। वकीलों द्वारा पेशी बदलवाते रहना, जज द्वारा उसकी स्वीकृति देते रहना, पक्ष-विरक्ष को विरम्य कराने की प्रवृत्ति, जज का अवकाश में होना, शौक सभा व अन्य अवसरों पर सुनवाई रोक देना आदि भी कारण बनते हैं। न्यायपालिका का अंग्रेजों जैसा पेटर्न बदलना चाहिये। वकील, सरकार व जज बैठ कर हमारी न्याय संहिताओं को अधिक व्यावहारिक बनायें तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट तक साधारण, सामान्य निर्धन व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता वह अत्यधिक व्यय-साध्य है, इस पर भी विचार होना चाहिये।

न्यायालय बेतहाशा बढ़े हैं परंतु न्यायालयों और जज की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। इस देश की परिस्थितियों में लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को अधिक ईमानदारी व परिश्रम से काम करना होगा, तभी समस्याएँ सुलझेंगी। सोशल मीडिया द्वारा उठाये गये बिंदु कितने सही व सार्थक हैं इन पर जन साधारण विचार करेगा ही, परंतु इतना तो सही है कि न्यायपालिका की कई कार्रवाइयों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है तभी पंच परमेश्वर बन सकेंगे।

कार्यपालिका में नौकरशाही की खुलकर आलोचना होती ही रहती है। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के उदाहरण भी सामने आते ही रहते हैं। उन पर कार्यवाई भी होती है, परंतु वह अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। लोगों में यह अवधारणा है कि बिना रिश्तत के अथवा बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। अपवादों की चर्चा तो सामान्यतः होती ही नहीं जो स्वाभाविक है। इसी प्रकार राजनेताओं के भ्रष्टाचारों की भी खूब चर्चा होती है। उनमें कई दंगी, अपराधी हैं, यह भी सच है। उनमें दल बदलने की प्रवृत्ति अधिक है। उनका कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं हैं, मात्र स्वार्थ ही प्रधान होता है, सेवा भावना नहीं। मीडिया में झूठी व फर्जी खबरें फैलाई जाती है। सोशल मीडिया को भी गैर ज़िम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी को विचार करना चाहिये। केन्द्रीय कानून मंत्री ने भी एक सुझाव दिया था कि जजों के चयन में वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। जजों के चयन में सिफारिश, पक्षपात, राजनीतिक दखल आदि का कोई स्थान न रहे और वह और पारदर्शी हो सके यह प्रयास हो जिससे कि हमारे पंच वास्तव में परमेश्वर बन सकें।

—अतिथि सम्पादक, कैलाश विहारी वाजपेयी, (स्वतंत्र चिंतक व लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरु-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वाथि सिद्धि योग रात्रि 7:३7 तक है। आज शुक्र उदय रात्रि 12:15 पर होगा। आज रुद्रत्रत (पीडिया त्रत), भगवान पुष्प दन्त जन्म और तप कल्याणक दिवस (जैन) है और भैरव षटगत उत्सव आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:1६ तक, चर 1०:54 से 12:13 तक, लाभ-अमृत 1२:13 से 2:51 तक, शुभ 4:1० से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:३0 से ३:00 तक। सूर्योदय ६:57, सूर्यास्त 5:३0

राशिफल

गुरुवार 24 नवम्बर, 2022

मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2०79, अनुराधा नक्षत्र सांय 7:३7 तक, अतिगंड योग दिन 12:19 तक, किस्त्रुघ्न करण दिन ३:02 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरु-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वाथि सिद्धि योग रात्रि 7:३7 तक है। आज शुक्र उदय रात्रि 12:15 पर होगा। आज रुद्रत्रत (पीडिया त्रत), भगवान पुष्प दन्त जन्म और तप कल्याणक दिवस (जैन) है और भैरव षटगत उत्सव आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:16 तक, चर 1०:54 से 12:13 तक, लाभ-अमृत 1२:13 से 2:51 तक, शुभ 4:1० से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:३0 से ३:00 तक। सूर्योदय ६:57, सूर्यास्त 5:3०

मे़ष
परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाणी की कटुता के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। परिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षा बढ़ेगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

धनु
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
परिवार में मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते व्यावसायिक कार्यों में प्रगति ठीक रहेगी। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तगत कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्याओं में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परिवर्तित से संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्मयोगी : घुमन्तू

“घुमन्तु“ अर्थात् जो अपने जीवन यापन तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घूमते रहते हैं। जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। जहाँ रात हो गयी, वहीं सो गये। यही इनके जीवन का यथार्थ है। यह यथार्थ बहुत कष्टदायक और चुनौतिपूर्ण है। जेल में सजा काट रहा कैदी भी इनसे कहीं अच्छा जीवन जी रहा है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान इनकी अनवरत गति को कोई रोक नहीं पाये। श्रीकृष्ण के “कर्म करते रहो“ के संदेश को घुमन्तु ने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है। घूमते-फिरते व्यवसाय करना, विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन से समाज का मनोरंजन करना, पशुपालन के साथ पशु व्यापार, परिवहन का कार्य करना, कारीगरी के माध्यम से घरेलू व कृषि उपकरणों के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र बनाना, राजा-महाराजाओं की सैन्य गतिविधियों में भाग लेना इनके मुख्य कार्य थे। घुमन्तु समाज एवं शेष समाज के आपसी संबंध मजबूत थे, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे।

दूसरी ओर शैक्षणिक उन्नयन के शिखर पर बैठा समूह भारतीय संस्कृति से दूर भाग रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को गर्व के साथ गले लगा रहा है। श्रेष्ठ कला एवं कौशल का पुजारी आजादी की जंग में बलिदान देने वाला जाबाज जनजाति समूह अंग्रेजी हुकुमत का शिकार भी रहा है। कष्ट का विषय तो यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है।

दूसरी ओर शैक्षणिक उन्नयन के शिखर पर बैठा समूह भारतीय संस्कृति से दूर भाग रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को गर्व के साथ गले लगा रहा है। श्रेष्ठ कला एवं कौशल का पुजारी आजादी की जंग में बलिदान देने वाला जाबाज जनजाति समूह अंग्रेजी हुकुमत का शिकार भी रहा है। कष्ट का विषय तो यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है।

“घुमन्तु“ अर्थात् जो अपने जीवन यापन तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घूमते रहते हैं। जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। जहाँ रात हो गयी, वहीं सो गये। यही इनके जीवन का यथार्थ है। यह यथार्थ बहुत कष्टदायक और चुनौतिपूर्ण है। जेल में सजा काट रहा कैदी भी इनसे कहीं अच्छा जीवन जी रहा है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान इनकी अनवरत गति को कोई रोक नहीं पाये। श्रीकृष्ण के “कर्म करते रहो“ के संदेश को घुमन्तु ने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है। घूमते-फिरते व्यवसाय करना, विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन से समाज का मनोरंजन करना, पशुपालन के साथ पशु व्यापार, परिवहन का कार्य करना, कारीगरी के माध्यम से घरेलू व कृषि उपकरणों के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र बनाना, राजा-महाराजाओं की सैन्य गतिविधियों में भाग लेना इनके मुख्य कार्य थे। घुमन्तु समाज एवं शेष समाज के आपसी संबंध मजबूत थे, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे।

आजादी के लिए 1857 की क्रांति में घुमन्तु समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों ने

वर्ष भर पक्षियों के कलरव से आबाद रहेगा मोरेल बांध

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के मोरेल बांध में आठ फीट पानी रिजर्व रखने के निर्णय के बाद पक्षी प्रेमियों एवं पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर देखी गई है। सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर जलवितरण समिति की बैठक के दौरान जिम्मेदारों के बीच यह निर्णय लिया गया। मोरेल बांध में देसी विदेशी विभिन्न पक्षियों के प्रवास के चलते पानी को रिजर्व रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी ताकि आने वाले पक्षियों से आसपास की खेत की फसल में लगे कीटो से नुकसान होने से बचाया जा सके एवं वहां पर आने वाले सेलानियों के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। बैठक सर्वाईमाधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सर्वाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें दौसा व सर्वाई माधोपुर के किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे।दौसा जिले से कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में उपखंड



मोरेल बांध में पर्याप्त जलभराव होने के चलते हजारों मील यात्रा तय कर आए राजहंस ग्रेटर फ्लैमिंगो कलरव करते हुए।

अधिकारी रामगढ़ पंचवारा तथा उपवन संरक्षक मौजूद रहे। डॉ सुभाष पहाड़िया ने कलेक्टर वीकेतन कुमार और पक्षिवेद डॉ सुभाष पहाड़िया सभागार में मोरेल बांध की जैव विविधता और

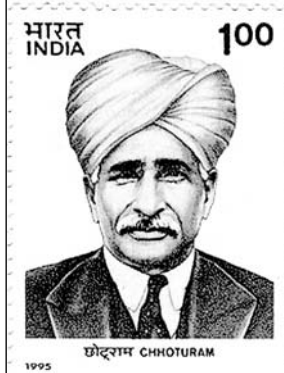
141वीं जयन्ती पर विशेष

किसान-मजदूर के दीनबंधु-चौधरी छोटूराम

चौधरी छोटूराम अदभुत व्यक्तित्व के धनी थे। किसान वर्ग द्वारा उन्हें कृषकों का मसीहा, रहबरे आजम तथा श्रमिक व दलित वर्ग ने दीनबंधु की उपाधियों से सम्मानित किया था। उनके लिए जाति या धर्म विशेष का कोई अन्तर नहीं था, जिसकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है, वही किसान है। चौधरी छोटूराम वास्तव में महान् कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त पंजाब, यूपी व राजस्थान (उत्तरी भारत) के किसान श्रमिकों तथा दलित शोषित वर्ग के हित में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से भूमि व ऋण उन्मोचन तथा लगान एवं अनेकों लागू-बाग करों से कानून बनवाकर, मुक्ति दिलायी। उनके सहयोग एवं सुधारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1937 में नाइट या सर की उपाधि से अलंकृत किया था।

छोटूराम का जन्म 24 नवम्बर, 1881 को माता हरकी देवी व पिता सुखीराम, ग्राम सांपला, तहसील झज्जर (रोहतक) वर्तमान हरियाणा में हुआ था। पिता कर्ज एवं मुकदमों में फँसे होने से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा झज्जर में तथा आगे की पढ़ाई क्रिश्चन मिशन स्कूल में हुयी और सन् 19०5 में सेन्ट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया था। उनका जन्म का नाम राम रिछपाल था। किन्तु परिवार में सबसे छोटे होने से उन्हें प्यार से छोटूराम बोला जाता था। स्कूल में दाखिले के वक्त भी यही नाम लिखा दिया गया। आगे छोटूराम के नाम से पंजाब-हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में किसान हमरा वर्ग के हितैषी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 19०7 में आगरा (यू.पी.) से कानून की पढाई कर डिग्री हासिल की।

विधि की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने, काला-कांकर के राजा रामपालसिंह के यहाँ निजी सचिव के रूप में कार्य किया और साथ-साथ यहीं से 19०7 में अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान’ का सम्पादन भी किया था। तदुपरांत 1912 में अपने मित्र चौधरी



यादराम सिंह यादव

लालचन्द के साथ आगरा में वकालत शुरू की एवं इसी वर्ष जाट महासभा का गठन किया। उसके बाद सन् 191६ में उन्होंने ‘जाट गजट’ नामक साप्ताहिक अखबार हिंदी में रोहतक से प्रारम्भ किया। वह अखबार में मजदूर-किसानों की समस्याओं को उठाते थे। अंग्रेजी सरकार तथा जमींदारों साहूकारों व सूदखोरों की गलत नीतियों के द्वारा शोषण दमन के विरुद्ध तीखे कटाक्ष भरे लेख लिखते थे।

‘जाट गजट’ हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो 1०6 वर्ष बाद आज भी प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र को अंग्रेजी दौर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन के समय पन्द्रह सौ प्रतियाँ छपना शुरू हुयी थी। इसका उद्देश्य तो विशेषकर जाट जाति के उत्थान के लिए था किन्तु बाद में वह जमींदार पार्टी का कट्टर समर्थक बन गया। छोटूराम ने किसानों की जमीन गिरवी रखने, उन्हें बंधुआ मजदूरी कराने के लिए साहूकारों द्वारा उड़ीपीडन करने के खिलाफ आवाज उठायी। अपने पत्र में वह भ्रष्ट सरकार की अफसरों, सूदखार, महाजनों के शोषण के विरुद्ध लेख लिखते थे। उन्होंने कोर्ट में भी इन शोषकों के विरुद्ध अनेक मुकदमें लड़े व जीते थे। सर छोटूराम ने अंग्रेजों से ही मोरों के शिकार पर भी पाबन्दी लगवा दी थी। इनके प्रमुख लेखों के शीर्षक ‘मोर बचाओ’, ‘ठगी के

बाजार की सैर’, ‘पाकिस्तान, जाट नौजवानों की जिंदगी के लिए नुखे’ आदि थे। सर छोटूराम अपने लेखों से साहूकार ही नहीं अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध भी आम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। छोटूराम गांधीजी के असहयोग आन्दोलन 192० से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि इससे गरीब किसानों व श्रमिकों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वह स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अलग हो गये। परन्तु मत भेदों के बावजूद वह गांधीजी के प्रशंसक भी थे। सर छोटूराम ने किसानों के हित में दो बड़े महत्वपूर्ण कानून अंगेजों से पास कराये थे। ‘411’ दी पंजाब रिलीफ इन्डेब्टेन्स एक्ट, 1934; ‘421’ दी पंजाब डेब्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 19३६, इससे पूर्व पंजाब लैंड रैबन्यू एमैन्डमेन्ट एक्ट 1929 भी पास कराया था। इन कानूनों के लागू होते ही किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली थी। इन कानूनों के तहत किसानों की कर्जांमुक्ति एवं जमींदारों-साहूकारों व सूदखोरों से गिरवी रखे जमीनें किसानों को वापस मिलीं एवं वे जमीनों के मालिक बन गये। इसके तहत किसानों द्वारा जमींदारों-साहूकारों से लिया गया ऋण नकद या जमीन गिरवी रखने पर ऋण को दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण को दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण एवं भूमि पुक्ती का प्रावधान किया गया था। इससे हजारों किसानों, जमींदारों,

खिलाफ स्वतंत्रता आन्दोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज किया। इतिहास में इनके बलिदान को पर्याप्त एवं प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया। उमा जी नाइक, भीमा जी नाइक, लक्ष्मीशाह बंजारा, गोविन्द गुरू, संत सेवालाल जी महाराज, अमरा भगत आदि घुमन्तु समाज के प्रमुख महानायक रहे हैं, जिन्होने सामाजिक कुरूपतियों को समाप्त करने के साथ-साथ आजादी के आन्दोलन के गौरवशाली सितारों भी थे।

देश में ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से जैसे-जैसे विकास का रथ आगे बढ़ ता गया ये जनजातियों अपने पारम्परिक व्यवसाय से हाथ धोती गयी। यातायात के आधुनिकीकरण की वजह से बंजारों का व्यवसाय कमजोर हो गया। तकनीकी विकास ने गाँडिया लोहारों को बेरोजगार कर दिया। स्पास्टिक के खिलाँनों ने कुचबन्दा समुदाय के मिट्टी के खिलाँनों को बाजार से बाहर कर दिया। कम्प्यूटर ने समुदाय की पेशियों को छीन लिया। टी.वी., मोबाइल, इन्टरनेट के युग में मनोरंजन के लिए बहुरूपियें, बाजीगर, नट या कालबेलियों की कला के लिए लोगों के पास समय नहीं है। धीरे-धीरे इन लोगों

की व्यावसायिक प्रासंगिकता शहर से कस्बों, कस्बों से गाँवों, गाँवों से दुर्गम स्थानों तक सिमटकर आया लगभग समाप्त ही हो चुकी है। विकास की आधुनिक दौड़ में घुमन्तु लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।

राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कर्मयोगी घुमन्तु को गरीबी से मुक्त करने के लिए रोजगार से जोड़ना होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घुमन्तु के घर तक पहुँचाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज बनाने होंगे। प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुँचाना होगा। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करनी होगी।

ब्रिटिश राज से पहले घुमन्तु जनजातियों का जीवन सम्पन्न और सम्मान जनक हुआ करता था। हमें वही सम्पन्नता और सम्मान लौटाना होगा। माननीया प्रोपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना घुमन्तु समुदाय की दशा एवं शिक्षा बदलने के क्रम में एक अच्छी खबर है।

—**डॉ. कैलाश सोडाणी, कुलपति-बर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**

प्रवासी पक्षियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया तथा बांध में 8 फिट पानी रिजर्व रखने की मांग रखी। जिसे आम सहमति से स्वीकार कर कलेक्टर द्वारा नहर खोलने के आदेश दिए। राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष पहाड़िया पिछले चार सालों से मोरेल बांध के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे। हाल ही में डॉ पहाड़िया द्वारा संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर भी बांध के जल को आठ फिट रिजर्व रखने की मांग की गई थी। डॉ सुभाष पहाड़िया ने बताया की मोरेल बांध में आठ फिट पानी रिजर्व रखने से पक्षी प्रेमी बहुत खुश है। अब यहाँ प्रवासी पक्षी स्वच्छंद विचरण कर पाएंगे। बांध में पानी रहने से पक्षियों के लिए हैबिटाट विकसीत होगा।कई पक्षी प्रजातियां यहाँ प्रवास करनेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में जीव जंतुओं के लिए पीने के पानी का संकट नहीं होगा। स्थानीय भू जल स्तर में वृद्धि होगी।

मूल्य 6 रु. प्रतिमन घोषित कर दिये। यह व्यवस्था ‘दाम-दू पट्टा’ कहलाती थी। इसके अलावा छोटूराम ने बालश्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर कानून बनाकर पाबन्दी लगायी। मजदूरों को काम के 8 घंटे तय किये गये एवं सप्ताह में एक छुट्टी का नियम बनवाया।

सर छोटूराम ने अंगेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी मांग पर 22,००0 से अधिक युवक सेना में भर्ती कराये। इनकी वफादारी से खुश होकर अंग्रेजों ने भांछडा नांगल बांध के निर्माण एवं सतलज नदी के पानी के लिए जिस पर बिलासपुर ‘एच.पी.’ के राजा का अधिकार था। छोटूराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर राजा से लिखित में समझौता कराके पानी का अधिकार प्राप्त किया था। उन्होंने दलित शिक्षित युवकों को ऊँचे-ऊँचे पद देकर अपनी उदारता व दलित प्रेम का परिचय दिया।

छोटूराम ने स्वयं एक गांव में जाकर अछूतों को कुएँ पर चढ़ाया जाकर पानी भरवाना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष/आन्दोलन करके तत्कालीन समय में प्रचलित साहूकारों जमींदारों द्वारा गरीब किसानों मजदूरों से वसूल जाने वाले अनेकों व्यवसाय कर एवं लागू-बाग आदि जैसे कुम्हारों पर ‘चाक-लाग’, भेड़ बकरी पालकों पर ‘कतरन लाग’, दलित बुनकरों पर ‘बुनकर लाग’, नाइयों पर ‘कतरन-लाग’ को खत्म करार के शोषण से मुक्ति दिलायी।

छोटूराम ने कौमी एकता के लिए सभी पिछड़ी जातियों को ‘अजगर’ नाम देकर, अत्र अहीर, जत्र जाट, गत्र गुर्जर एवं रत्र राजपूत और रोडे सभी कृषक जातियों को संगठित कर एक एकाने का प्रयास किया। वह साम्प्रदायि एकता के भी प्रतीक थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे किन्तु उन्होंने मजदूर किसानों के हित में असाधारण कार्य किये। सन् 19३7 में झज्जर के डुब्बारा नेता चौधरी छोटूराम पहले विकास, शिक्षा व राजस्व मंत्री बने थे। उस समय अंग्रेजी सरकार ने किसानों की उपज गेहूँ की खरीद का

—**यादराम सिंह यादव, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार**

अधिकारियों की मौजूदगी में खाद बांटी

वैरा। बुधवार को उपखंड मुख्यालय पर कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में खाद का निर्धारित दर पर वितरण किया गया जहां किसानों से 267 रुपए प्रति बैग के कीमत के आधार पर राशि ली गई।बुधवार को कस्बा वैर के बस स्टैंड पर स्थित सेगर वाल खाद बीज की दुकान पर खाद के कट्टे आने की सूचना मिली जिस पर कस्बा सहित ग्रामीण अंचल से किसान खाद लेने के लिए पहुंचे।

कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में एसडीएम मुनिदेव यादव के निर्देशन में खाद के कट्टो का वितरण किया गया। जहां 950 खाद के कट्टे निर्धारित दर 267 प्रति बैग की दर से वितरित किए ।

गत दिवस सहायक कृषि अधिकारी मुनीम सिंह गुर्जर ने भी उपखंड मुख्यालय पर खाद विक्रेताओं की बैठक लेते हुए निर्धारित दर पर खाद बेचने तथा खाद के साथ अन्य लगेज नहीं देने के लिए पाबंद किया था।जिस पर बुधवार को निर्धारित दर से खाद के बैग किसानों को उपलब्ध किए।बताया जा रहा है की इसके अलावा अन्य खाद बीज की दुकानों से भी करीब 2000 खाद के बैग वितरित किए।

‘महाराजा अग्रसेन डायरेक्ट्री का प्रकाशन होगा’



महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान राजेन्द्र नगर बैठक अध्यक्ष रवि गुप्ता (बाएं से दूसरे) की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

भरतपुर (निस)। महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान राजेन्द्र नगर जवाहर नगर के कार्यकारी सदस्य, संरक्षक मंडल, मार्ग दर्शक एवम विशेष अर्मांत्रित सदस्यो की मीटिंग संस्थान अध्यक्ष डा रवि गुप्ता की अध्यक्षता में होटल प्रताप रीगल में आयोजित की गई। जिसमें संस्थान द्वारा आगामी महीनों में किए जाने कार्यक्रमों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। संस्थान महामंत्री राकेश गुप्ता ने बताया कि इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा संस्थान क्षेत्र में रहने वाले समाज के सभी सदस्यों की

डायरेक्टरी जिसमे की परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा, प्रकाशन कर जनवरी 2023 मे विमोचन किया जाएगा। इसके लिए संपादक मंडल का गठन किया, जिसमे जी सी गोयल, डा अशोक बंसल, कपूर चंद गुप्ता , राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अनिल गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि डायरेक्ट्री का प्रकाशन संस्थान सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट्री में विज्ञापन प्रकशित किए जायेंगे। विज्ञापन संकलन की जिम्मेदारी कृष्ण

कांत गर्ग, हेमराज गोयल, डा एल पी गुप्ता, पंकज सिंघल एडवोकेट, एवं अन्य सदस्यो को दी गई। मीटिंग में संस्थान के जरूरत मंद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पूर्व विधायक विजय बंसल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, जिला अग्रवाल महासभा भरतपुर, बयाना इकाई, नदबई इकाई, कपूर चंद माचिस वाले, विशान गुप्ता पी एन बी एवं अन्य लोगो का आभार व्यक्त किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।

धरना दूसरे दिन भी जारी

हिण्डौन सिटी । राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चा की ओर से बुधवार को दूसरे दिन रोडवेज डिपो के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा संगठनों में सीटू, इंटक, कल्याण समिति, एटक के पदाधिकारी एवं रोडवेज के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।

मोर्चा से जुड़े पूरनचंद शर्मा ने बताया कि रोडवेज में 10 हजार नई भर्तियां लागू करने 2 हजार नई बसें खरीदने, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित 21 सूत्रीय मांग के संदर्भ में राजस्थान सरकार को संयुक्त मोर्चा की ओर से कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उक्त मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने से रोडवेज के संयुक्त मोर्चा की ओर से रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है। साथ ही बताया गया कि बुधवार को मुख्यमंत्री व प्रतिनिधिमंडल के मध्य वार्ता होनी है। यदि सहमति नहीं बन पाई, तो गुरुवार से प्रदर्श भर में रोडवेज के सभी कर्मचारी चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। हिंडौन डिपो के प्रबंधक गजानन मीणा ने पदाधिकारियों से वार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की।

कार्यशाला में जीएसटी में होने वाले बदलाव बताए



जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता एसजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त राघवेंद्र सिंह यादव ने की।

बदलावो के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के नियमों में किए गए संशोधनो के बारे में सभी व्यवसायों को जानकारी उपलब्ध करवाया जाना था। जीएसटी में विवरणी अनुपालना, बिजनेस ऑडिट, रिटर्न स्कूटनी, जीएसटी रिफण्ड,

आईटीसी एवं समय पर रिटर्न भरने के फायदे की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई गई। तरुण कुमार पाण्डेय, उपायुक्त वृत्त अ भरतपुर एवं डॉ. आषीष जैन, उपायुक्त, वृत्त सवाईमाधोपुर के द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधनो के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई।

शपथ ग्रहण समारोह आयोजित



हिण्डौन सिटी में जांगिड ब्राह्मण महासभा की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ।

हिण्डौन सिटी । के किशन नगर स्थित जांगिड विकास संस्थान में अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा की जिला कार्यकारिणी के शपथ टाहण समारोह आयोजित हुआ। महासभा के करौली जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि समारोह में अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्ष वाल ने की जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उज्ज्ज्केशन ट्रस्ट के प्रधान कांति प्रसाद टाङ्गर रहे। समारोह में

सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला, महिला जिला अध्यक्ष राजकुमारी, भरतपुर के जिला अध्यक्ष सोहनलाल, दौसा के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद, महासभा के उप प्रधान सवाई माधोपुर निवासी मूलचंद, घनश्याम, राजेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समाज के उप प्रधान मूलचंद भारतीय, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक धर्मराज जांगिड , उपप्रधान रिटायर्ड

तहसीलदार घनश्याम, मुखारी लाल देसाई, समाजसेवी मनोहरी लाल, श्री लाल, गोपाल, प्रकाश, राजेंद्र, राधेश्याम, छिंगाराम, युवा जिला अध्यक्ष रितेश व घनश्याम आदि ने अतिथियों का साफा माला पहना कर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल ने समाज विकास एवं एकजुटता की बात कही।

ई-मित्र का जिला कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

भरतपुर (निस)। जिला कलक्टर आलोक रंजन बुधवार को पंचायत समिति रूपवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानुआ, सीएचसी रूपवास, इंदिरा रसोई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांटी योजना के कार्यों, ई-मित्र कियोस्क, उपखण्ड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय तहसील कार्यालय, राशन की दुकान, श्री शिव शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह का आकस्मिक अवलोकन किया। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने राउमवि खानुआ का निरीक्षण कर शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये तथा शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए विद्यालय की कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान की क्लास लेकर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रश्न पूछे। उन्होंने विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण कर सफाई कराने एवं विद्यार्थियों को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जिससे उल्लेख के साथ-साथ शारीरिक विकास भी हो सके। उन्होंने

मेहन्दी प्रतियोगिता आयोजित

भरतपुर (निस)। रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिषद के तत्वाधान में गृहविज्ञान विभाग द्वारा मेहन्दी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज प्राचार्य डॉ. धीरेन्द्र देवर्शि ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्राओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहता है। अकादमिक प्रभारी मधु पर्मा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए मेहंदी में डिजाइन का चुनाव, व बनाने में लाइनों व भरने सम्बन्धी जानकारी दी। कार्यक्रम प्रभारी साधना शर्मा के निर्देशन में समस्त कार्य सम्पन्न किया गया तथा उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं को रोजगार के लिये प्रेरित करते है। मेहंदी में प्रथम रम्यी, द्वितीया रितिका दिवाकर, हिना, तृतीय मोनिका, सुश्रिट अग्रवाल व सत्वन पुरस्कार अंजलि ने प्राप्त किया। निर्णायक मण्डल में डॉ. मीनू अरविन्द, डॉ. अंजू पाठक आदि थे।

चर्चा है कि इसी के साथ क्षेत्र के पुराने बरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव से दरकिनार करना एवं लंबे समय से उनके प्रति उदासीनता भरा रवैया भी नुकसानदेह साबित हो सकता है । इस पंचायत समिति सदस्य वार्ड 16 के हो रहे उपचुनाव में भाजपा की ओर से गोरन्ती देवी सैनी एवं कांग्रेस से चमेली देवी माली चुनावी मैदान में है । चर्चा है कि दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी के पति का राशन डीलर होना एवं क्षेत्र में राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत के साथ लंबे समय तक निर्लंबित रहने के चलते उपचुनाव में कांग्रेस को पंचायत समिति सदस्य पद वाद 16 की सीट

जागरूकता रैली रवाना

भरतपुर (निस) । आयुर्वेद विभाग के द्वारा स्थानीय एमएसजे कॉलेज ग्राउण्ड में लगाए जा रहे राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का अधिकाधिक प्रचार प्रसार एवं जनभागीदारी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के द्वारा लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। आरोग्य मेला का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके इसी कल्पना को लेकर आयुर्वेद विभाग के द्वारा बुधवार को आरोग्य मेले के प्रचार के लिए रैली निकाली गई। रैली को नगर गिंगम महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। रैली में के आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक, कर्मचारी एवं आयुर्वेद कॉलेज की छात्र छात्राएं मौजूद रही। जिनके द्वारा आरोग्य मेले के पम्पलेट बाजार में लोगों को वितरित किए गए एवं आरोग्य मेले का लाभ लेने की अपील की गई। स्थानीय एमएसजे कॉलेज ग्राउण्ड में 24 से 27 नवम्बर तक आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। रैली कुम्हेर गेट से प्रारंभ हुई जो कोतवाली, लक्ष्मणमंदिर, गंगा मंदिर से मथुरा गेट होते हुए बिजलीघर पर सम्पन्न हुई। रैली के दौरान आयुर्वेद आरोग्य रथों के द्वारा भी लाउड स्पीकर से आरोग्य मेले का प्रचार प्रसार किया गया।

बेहतर होंगी चिकित्सा सुविधाएं

करौली (नि.स.)। कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालय में अब एमबीबीएस चिकित्सक की भी सेवाएं मिलने से डॉंग क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री कैलादेवी टेंपल ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक महेश चंद शर्मा ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालय में डॉ. अरविंद शर्मा एमबीबीएस, एमडी ने पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के रूप में चिकित्सालय में सेवाएं देना प्रारंभ कर दी है ।

उन्होंने बताया कि कैलादेवी के अलावा आसपास के गांव के लोगों को अब शिविर के अलावा प्रतिदिन योग्य चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी भविष्य में चिकित्सालय में और भी विस्तार किया जाएगा तथा रोगियों को चिकित्सालय में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

उन्होंने बताया कि पैथोलॉजी टेस्ट के अलावा एक्स-रे आदि की अतिरिक्त सुविधाएं पहले से ही सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं लेकिन अब एक एमबीबीएस चिकित्सक के कार्यभार ग्रहण कर लेने से क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा।

सार-समाचार

2 लाख रुपए की सहायता

सवाई माधोपुर । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शाखा के ग्राहक बीमाधारी राधेश्याम माली पुत्र हीरालाल माली निवासी कुस्तला की मृत्यु के उपरांत मृतक की पत्नी मनभर देवी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है। बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रीय टापीण बैंक शाखा कुस्तला के शाखा प्रबंधक सुरेश चंद गुप्ता ने बताया कि कुस्तला गांव के ठाहक राधेश्याम माली पुत्र हीरालाल माली ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 की किस्त में बीमा करवाया था। उनकी दिनांक 21 सितम्बर 2022 को अकस्मात मृत्यु हो गई थी। बैंक द्वारा बैंक की बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट एलआईसी को ठाहक की मृत्यु की सूचना दी गई जिस पर बीमा कंपनी द्वारा नामित एवं मृतक की पत्नी के नाम 2 लाख का क्लेम पारित किया। बुधवार को 2 लाख की राशि का चेक प्रदान कर सहायता राशि भेंट की गई।

मीणा होंगे नये जिला शिक्षा अधिकारी

करौली (नि.स.)। शिक्षा ग्रुप-2 के संयुक्त शासन सचिव ने तबादला सूची जारी करते हुए करौली शिक्षा अधिकारी के पद पर राधेश्याम मीणा को लगाया है। ज्ञात रहे की करौली के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे जिनका तबादला सीबीआईओ फतेहगढ़,जैसलमेर कर दिया गया है। वही उनके स्थान पर आदेशो की प्रतिक्षा मे चल रहे (एपीओ)राधेश्याम मीणा को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर लगाने हुये संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग ग्रुप-2 प्रवीण कुमार लेखरा ने 7 दिवस मे कार्य ग्रहण कर पालना से अवगत कराने के निर्देश दिये है।

बैठक आज

करौली (नि.स.) अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि जिले के विकास कार्यों व फ्लैशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता मे आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित की जायेगी।

झूठे केस में फंसाने के आरोप में महिला गिरफ्तार

करौली (नि.स.) रेप जैसे गंभीर आरोप में फंसाने का डर दिखाकर रूपये हड़पने की आरोपी एक महिला को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करौली कोतवाली थाना अधिकारी डॉ. उदयभान ने बताया की करौली थाना क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोर ने गत 6 अक्टूबर को करौली थाने में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया की उनकी करौली के सदर बाजार में बर्तनों की दुकान है।

दुकान पर एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी पत्नी माधोसिंह गुर्जर निवासी छदवाड थाना बालघाट हाल निवासी शुक्ल खिडकिया करौली में रहती है। वो दुकान पर आई और दुकान से बर्तन खरीद लिये तथा पैसे माँगने पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगी। साथ ही डरा धमका कर 5 लाख रुपये की माँग की।

महिला पूर्व में भी मुकदमा दर्ज कराने का भय दिखाकर 10-12 हजार रूपये ऎठ चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो मामला सही पाया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला लक्ष्मी पति माधोसिंह गुर्जर निवासी छन्दवाड थाना बालघाट को गिरफ्तार कर लिया।

भाजपा प्रत्याशी को पति के आकस्मिक निधन का मिल सकता है फायदा

■ बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र में वार्ड नम्बर 16 के रिक्त हुए पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव 25 को होंगे

का निकलना खटाई में दिखाई दे रहा है । दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े किए गए प्रत्याशी का पूर्व में भाजपा के दिवंगत प्रत्याशी मनराज सैनी की पत्नी होना एवं भाजपा के पंचायत समिति सदस्य का असामयिक निधन के बाद किसी तरह पिछला कार्याकाल विवाद में नहीं रहना व भाजपा के पंचायत पर लडके भाजपा से जीती पंचायत समिति सदस्य के आकस्मिक निधन से मिल रही सहानुभूति कांग्रेस के चुनावी राह में पैदा हुए कोड में खज का काम कर रही है । चर्चा है कि इसी के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा विवाद भी किसी से छिपा हुआ है ।

ऐसे में स्थानीय विधायक इंदिरा

मीणा द्वारा सचिन पायलट के संगठन नेतृत्व के चलते एवं पायलट समर्थक का दिखावा करते हुए कांग्रेस का टिकट लेकर विधायक बनने के बाद अचानक पैदा हुए सियासी संकट में गहलोत के पाले में आने की घोषणा भी पायलट समर्थकों में आक्रोश का कारण बना हुआ है ।

इस स्थिति में विधायक इंदिरा मीणा द्वारा उतारे गए कांग्रेस प्रत्याशी से नाराजगी एवं टिकट के तथाकथित तौर पर हुए गलत चुनाव के चलते नुकसान होना चर्चा का विषय बना हुआ है वहीं पंचायत समिति बामनवास के वार्ड 16 में हो रहे उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय होने के कारण विधायक इंदिरा मीणा भी उम्मीदवार को जीताने के लिए घर-घर संपर्क कर वोट मांग रही है तो दूसरी ओर भाजपा के नेता भी खुद के प्रत्याशी को जीताने के लिए घर-घर जाकर वोट मांग रहे है ।

बहरहाल उपचुनाव में मतदान के बाद आने वाले परिणाम बड़े चौंकाने वाले हो सकते है । ऐसे में मतदान के बाद परिणाम ही तय करेंगे कि उपचुनाव में जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर बंधेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब होती है ।

कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक:-1074

दिनांक: 22.11.2022

सार्वजनिक आपत्ति विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखित आवेदकों के आगे बर्णित स्थान पर 9/10वीं के तहत पट्टा चाहा गया है जो निम्न है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	राजस्व ग्राम	खसत नं.	क्षेत्रफल वर्गगज	आवासीय व्यवसायिक
1.	शेख अमीरुद्दीन पुत्र नजीरुद्दीन	भिर्जोपुर	162	333.33	आवासीय
2.	विश्राम मीना पुत्र तुलसीराम मीना	जेईईकलां	5699.5700.5701	133.33	आवासीय
3.	पुखराज मीना पुत्र प्रभूलाल मीना	जेईईकलां	5594	133.33	आवासीय
4.	पुखराज मीना पुत्र प्रभूलाल मीना	जेईईकलां	5594	133.33	आवासीय
5.	अनीता कुमार मीना पुत्र रविन्द्र कुमार	डिबस्या	1128	318.33	आवासीय
6.	कमलेश कुमार वैष्णव पुत्र राधेश्याम	बादसालोदा	54,55	208.33	आवासीय
7.	मस्ता गुप्ता पत्नी गौरी शंकर गुप्ता	महुखुर्द	239.240	399.99	मिश्रीत
8.	कवितो गोयल पत्नी पुरूषोत्तमदास	भिर्जोपुर	282, 284	111.11	आवासीय
9.	विनीता अग्रवाल पत्नी योगेश कुमार	भिर्जोपुर	375	133.33	आवासीय
10.	लक्ष्मी देवी पत्नी अवध बिहारी	महानन्दपुर	276	2893.33	मिश्रीत
11.	भूपेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र किरोडी लाल	महानन्दपुर	278	266.66	आवासीय
12.	नेमी चन्द शर्मा व त्रिलोक चन्द पुत्रों पाख्य लाल शर्मा	सालोदा	387, 391, 407, 408	137.77	आवासीय

अतः जिस किसी व्यक्ति को उक्त खसरा नम्बरों में पट्टा देने में किसी प्रकार का आपत्ति हो तो 7 दिवस में परिषद में उपस्थित होकर लिखित रूप में पेश कर सकते है। अंतर्द अवधि में आपत्ति पेश नहीं होने पर आवेदनकर्ता को भूमि का निपटामानुसार आवासीय/व्यवसायिक पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जाएगी इसके पश्चात कोई भी आपत्ति नही सुनी जायेगी। सूचित रहे।

आयुक्त

नगर परिषद, गंगापुर सिटी

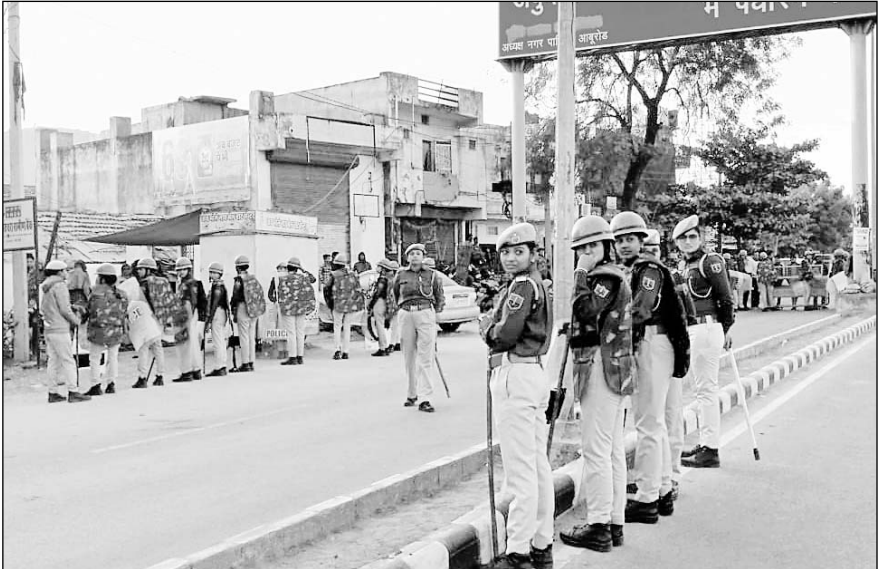
मंदिर हटाने पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

एसपी, सीओ सहित चार पुलिसकर्मी चोटिल

आबूरोड, (निसं)। सिरोही जिले के आबूरोड के सातपुर में बुधवार को तालाब की पाल पर बने मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर व तालाब पर बने अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। बुधवार सुबह 6 बजे से पुलिस का भारी जांका सातपुर पहुंचा। जहां एडीएम कालूराम खोड के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस व प्रशासन की भारी मौजूदगी के बीच लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों की भीड़ मौके पर जमा होती लगी।

मौके पर पहुंचे भाजपा ग्रामीण मण्डल के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने प्रशासन से हनुमान जी की मूर्ति को अन्य मंदिर में शिफ्ट करने को कहा जिसपर पुलिस प्रशासन की टीम ने मूर्ति को निकाल सातपुर के अन्य मंदिर में शिफ्ट की। मौके पर जेसीबी की मदद से मंदिर को तोड़ा। वही तालाब की जद में आ रहे अन्य अतिक्रमण को भी मौके से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान आबूरोड-सातपुर मार्ग पर लोग जाम लगाकर बैठे रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर बाद भाजपा व हिन्दू संगठनों के नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के विरोध में सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी दी। पर स्थानीय लोग सड़क पर जमे रहे।

पुलिस ने लोगों से समझाइश की पर लोग नहीं माने तो पुलिस ने सड़क पर बैठें लोगों को उठाया और अपने घर जाने को कहा। आक्रोशित लोग जैसे



पथराव की घटना के बाद आबूरोड के सांतपुर में पुलिस बल तैनात रहा।

ही गलियों में गए तो गलियों में जाकर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एसपी देवाराम चौधरी के नाक पर चोट लगी। वहीं माउंट आबू सीओ योगेश शर्मा के मुँह पर चोट लगी। साथ ही अन्य दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने मौके पर हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया। गलियों में जाकर पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर कुछ देर के लिए बने तनाव के बाद पुलिस ने शांति स्थापित की। वही इस दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करने

आए भाजपा नेता अरुण परसरामपुरिया पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर डॉ. भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मौके पर घटना के बारे में जानकारी लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने घायल पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बरे में जानकारी ली।

जिला कलेक्टर डॉ. भवरलाल चौधरी ने बताया कि सांतपुर निवासी कांतिलाल उपाध्याय द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि तालाब की 14

बीघा भूमि पर अतिक्रमण है जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं पर याचिकाकर्ता द्वारा भी अतिक्रमण कर मकान बनाया गया जिसपर पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके विरोध में गुरुवार को आबूरोड बन्द का आह्वान किया गया है बन्द में सभी हिन्दू संगठन शामिल है।

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और प्रशासन द्वारा मंदिर हटाए जाने की जानकारी मिलने पर रेवदर विधायक

■ आबूरोड में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया हनुमान मंदिर

जगसीराम कोली, आबू-पिण्डवाडा विधायक समाराम गरासिया आबूरोड पहुंचे। जहां उन्होंने मंदिर तोड़े जाने और पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का विरोध किया। विधायक जगसीराम कोली ने कहा की सरकार हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और विरोध करने पर लाठीचार्ज की जा रही है। समाराम गरासिया ने कहा कि यह सरकार हिन्दू विरोधी है।

विधायक ने आरोप लगाया की आज जिस प्रकार से घरों में घुस कर पुलिस ने बबरतापूर्ण कार्रवाई की है। यह उचित नहीं हो सकता है। मंदिर के टूटने से कुछ आक्रोशित भीड़ ने गत कदम उठाया हो पर पुलिस को समझाइश से मामला सुलझाया जा सकता था। बच्चों और महिलाओं पर घरों में घुस कर मारपीट की गई है। जिसकी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन से मांग की के जिन स्थानीय लोगों को पकड़ा और भाजपा पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है पर वो पथराव में शामिल नहीं थे उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा कल आबूरोड बन्द का आह्वान किया गया है।

एक रुपया अधिक वसूला, अब चुकाने होंगे 1000 रु.

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का फैसला

जोधपुर, (कासं)। ग्राहक से सामान पर अंकित मूल्य से एक रुपया अधिक वसूल करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। जागरूक ग्राहक ने इसका विरोध करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत पेश की। इस पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक रुपए के बदले अब एक हजार रुपए ग्राहक को वापस लौटाने का दुकानदार को आदेश दिया है।

मामले के अनुसार पाल लिंक रोड निवासी प्रणव मेहता ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मुख्य पाल रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पोइंट शोपिंग स्टोर से उसने मार्च, 22 में टूथ ब्रश खरीद किया। जिस पर 39 रुपये मूल्य अंकित होने के बावजूद बिल में 40 रुपये वसूल किये गये। मैनेजर को शिकायत करने व कानूनी नोटिस दिलाने के बावजूद अधिक ली गई राशि वापस नहीं लौटाई गई। उन्हे उसका मजक उड़ाया गया। विपक्षी रिलायंस शोपिंग स्टोर द्वारा ज़बाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उन्हे स्टोर के नियमों के अनुसार अधिक राशि वसूल होने पर उनके मैनेजर द्वारा क्षमा मांगते हुए राशि लौटाने के

अलावा ग्राहक को एक सौ रूपए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैठ ने सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि परिवादी द्वारा मौखिक रूप से मांग करने व अधिवक्ता से नोटिस दिलवाने के बावजूद विपक्षी द्वारा राशि लौटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह विवाद मात्र एक रुपये की मामूली राशि की अधिक वसूली का नहीं होकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण से संबंधित है। विभिन्न आइटमों के इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा छोटी-छोटी राशि के रूप में ग्राहकों से अधिक वसूली करने की नाजायज प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। आयोग ने विपक्षी

रिलायंस स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी मानते हुए एक रुपया की राशि वापस लौटाने के अलावा परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी को कानूनी कार्यवाही का खर्चा भी विपक्षी स्टोर द्वारा ही भुगतान किया जावेगा।

पुलिस कांस्टेबल की वाहन की चपेट में आने से मौत

टोंक, (निसं)। पुलिस कांस्टेबल हरिराम वर्मा की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार पीपलू थाना क्षेत्र के नानेर निवासी हरिराम वर्मा पुत्र फूलचंद रैगर जो कि बूंदी पुलिस में कांस्टेबल है, अपने मित्र मुकेश पुत्र प्रहलाद रैगर 28 साल के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि काशीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हरिराम की मौत हो गई और मुकेश घायल हो गया। पीपलू पुलिस ने मृतक कांस्टेबल को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरु कर दी।

टोंक, (निसं.)। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अ.नि.) प्रकरण टोंक ने मेहंदवास क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले में एक जने की केरोसिन डालकर जला देने के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या के दर्ज प्रकरण में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 आरोपियों को बरी करने के आदेश पारित किए।

एसी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश चौपडा ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि 3 नवम्बर 2015 को दोपहर 11 बजे जमीनी विवाद के मामले में आरोपी परिवादी नाथूलाल बैरवा पुत्र कंवरी लाल बैरवा निवासी मेहंदवास के खेत पर सरसों की उगी फसल को ट्रैक्टर से



हत्या के दर्ज प्रकरण में आजीवन कारावास के आरोपी।

नष्ट करने गए, जिस पर परिवादी के बेटे राजाराम ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने पहले मारपीट की और ट्रैक्टर के टब में से केरोसिन की बोतल

निकालकर राजाराम पर डाल दी और माचिस लगाकर जला दिया। इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस में राजाराम की तीन-चार

दिन के बाद मौत हो गई। राजाराम ने मौत से पहले पुलिस को पचा बयान दिया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। जिस पर पुलिस ने 31

दिसम्बर 2012 को एफआर लगा दी थी, जिस पर न्यायालय ने 16 सितम्बर 2016 को पुनः प्रसंज्ञान लिया, जिस पर मामला धारा 302 में दर्ज किया गया। जिस पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से चार आरोपियों मनराज, रामसहाय उर्फ राजू, हंसराज पुत्रान जमनालाल, महावीर पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहंदवास को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किए। वहीं इस मामले में शेष 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रुपा देवी, गोपाली, गोपीलाल को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए।

विद्या के मंदिर में शराब-मांस पार्टी

श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला

बीकानेर, (निसं)। श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल की क्लास में स्टूडेंट्स के होश उस समय उड़ गए, जब टेबल पर चिकन-मटन के टुकड़े मिले। इतना ही स्कूल के बाहर शराब की बोतलें भी पड़ी मिली। इसके बाद से स्टूडेंट्स और अभिभावकों में आक्रोश है। बुधवार सुबह श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। शैव दरबार के लिए प्रसिद्ध तोलियासर के सरकारी स्कूल में मंगलवार को मांसाहार किया गया। इस

दौरान शराब पार्टी भी होने की आशंका है। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 के कमरा नम्बर 17 में मांस के टुकड़े मिले थे। साथ ही रोटी व रोटी को पैक करने वाले कागज भी मिले। मौका देखने से पता लगता है कि अज्ञात लोगों ने यहां रात में मांसाहार किया। कुछ लोग क्लास रूम का कुंडा तोड़कर भीतर घुसे हैं। खाना खाने के बाद हड्डियां, मांस, तंदूरी रोटी आदि वहीं फेंक दिए। स्टूडेंट्स ने ये सब देखा

■ स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचे तो टेबल पर पड़े थे चिकन-मटन के टुकड़े, स्कूल के बाहर शराब की बोतलें

तो प्रिंसिपल व टीचर्स को सूचना दी। सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी सिंह राजपुरोहित सहित अनेक ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सभी ने रोष जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजपुरोहित

ने कहा कि पूर्व में भी पुलिस को स्कूल में नल आदि तोड़ने की सूचना दी थी परंतु कार्रवाई नहीं हुई।

स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौका मुआयना किया गया। इससे पहले दस सितम्बर को इसी स्कूल में अज्ञात लोगों ने घुसकर कमरों के ताले तोड़ दिए थे। बच्चों के उपयोग की तब स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को रिपोर्ट दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ही कारण है कि चोरों और अस्माजिक तत्वों के हाँसे बढ़ते जा रहे हैं।

373 बीघा चरागाह पर बोई गई फसल नष्ट की

मालपुरा, (निसं)। राजस्थान सरकार

ने बीसुका उपाध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत का निस्तारण करते हुए एसडीएम केलाश नारायण मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को 373 बीघा सिवायचक व चरागाह भूमि पर बोई गई फसल को जेसीबी व ट्रैक्टरों सहित मवेशियों की सहायता से नष्ट कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

नायब तहसीलदार केलाश नारायण मीणा ने बताया कि चरागाह पर अतिक्रमण कर अतिक्रमियों द्वारा फसल जुताई करने की मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए बुधवार को सरपंच उम्मेद सिंह, पटवारी इन्द्रा चौधरी, लावा पटवारी दिनेश सैनी, कडीला पटवारी बाबूलाल वर्मा, कलमंडा श्रवण लाल बाकडीवाल, चबराना गिरदावर गोपाल

■ मालपुरा के चबराना गांव में राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन

खंगार, लावा गिरदावर राजेश कुमार मीणा, डिग्री थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, रामसिंह व मालपुरा आरएएसजी जवानों के कड़े जापे की मौजूदगी में 11 ट्रैक्टरों व जेसीबी मशीनों की सहायता से खड़ी फसल को नष्ट किया गया एवं मवेशियों को फसल में छोड़ा गया। प्रशासनिक अमले व कड़े पुलिस जापे की उपस्थिति में 373 बीघा चरागाह को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही की गई जो कि गुरुवार को भी जारी रहेगी।

कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द

क्रमांक:- जिपरा/क.लि.भर्ती-2013/प्र.सु.हि./2022-23/1940 दिनांक:23.11.2022

विज्ञप्ति

जिला परिषद राजसमन्द द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त अस्थायी प्रतीक्षा सूची दिनांक 9-11-2022 को जारी कर दिनांक 17-11-2022 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त अतिरिक्त अस्थायी प्रतीक्षा सूची दिनांक 23-11-2022 को जारी कर विभागीय पोर्टल www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर अपलोड हेतु प्रेषित कर दी गई है एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चप्पा की गई है। उक्त विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड अतिरिक्त द्वितीय प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित क्र.सं. 1 से 100 तक के अभ्यर्थी दिनांक 28-11-2022 एवं क्र.सं. 101 से शेष अभ्यर्थी दिनांक 29-11-2022 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय समय तक कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द के सभागार में अभ्यर्थी अपने साथ आवेदन पत्र मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित प्रति, वांछित शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करावे। सम्बन्धित अभ्यर्थी के निर्धारित दिनांक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

(उत्साह चौधरी) IAS, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द

ग्रेवल सड़क का निर्माण किए बिना उठा लिया लाखों रुपये का भुगतान

सायला, (निसं)। सायला के निकट तूरा ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाए बिना लाखों रूपए भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तूरा ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 14.78 लाख रूपये राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन माह फरवरी 2022 तक उक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया गया था जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला द्वारा 8 फरवरी 2022 को ग्राम विकास अधिकारी सुनील चौधरी को नोटिस भेजकर उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही नोटिस प्राप्त के तीन दिवस के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करवाने का ठोस कारण सहित प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

लेकिन ग्राम विकास अधिकारी एवं ठेकेदार की कथित मिलीभगत के चलते उक्त ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य कागजों में ही पूर्ण बताकर दिनांक 29 मार्च 2022 को करीबन 7 लाख 20 हजार रूपये का भुगतान फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक करीबन 4-5 साल से कोई ग्रेवल सड़क मार्ग नहीं बनाया गया है



सायला के निकटवर्ती तूरा-सोनारियां ग्रेवल सड़क मार्ग पर रेत जमी हुई है।

और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाए भुगतान उठाकर सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही है।

इस प्रकार किया भुगतान:- ग्राम

पंचायत तूरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सड़क निर्माण के नाम पर फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में 21 अक्टूबर 2022 को बिल संख्या 3 व्यय राशि 242497, बिल संख्या 4 व्यय राशि

242497 एवं बिल संख्या 5 व्यय राशि 235106 का बिल भुगतान किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत तूरा द्वारा कुल राशि करीबन 7 लाख 20 हजार रूपये का फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में भुगतान किया गया। वही उक्त बिल 29

■ ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक करीब 4-5 साल से कोई ग्रेवल सड़क मार्ग नहीं बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है

मार्च 2022 को भुगतान के लिए ऑनलाइन अपलोड किए गए थे।

जगह जगह बने गड्डे व रेत जमा:- तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल मार्ग पर जगह-जगह गड्डे बन गए हैं तथा रेत पड़ी है। जिससे वाहनचालकों को आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़क किनारे बबूल की कंटली झाड़ियां उगने से रास्ता संकरा हो गया है। जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को ग्रेवल सड़क मार्ग के बीचों-बीच चलना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर राजकीय विद्यालय सोनारियां भी आया हुआ है तथा कई कृषि बेरे भी स्थित हैं। ऐसे में इस मार्ग से आवागमन के दौरान विद्यार्थियों एवं किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बलवंतसिंह दहिया, उपसरपंच तूरा का कहना है कि तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सड़क का निर्माण किए ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जिसकी विभागीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सुनील चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी तूरा ने बताया कि तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक तीन वर्ष पहले ग्रेवल सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी जो मार्च 2022 में बनाया गया था तथा भुगतान किया गया है। अगर ग्रेवल सड़क नहीं बनी है तो देखते हैं।

मनमोहन मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला ने कहा कि यह मामला मेरी जॉइनिंग से पहले का है। जिसकी जानकारी लेता हूँ। अगर बिना ग्रेवल सड़क निर्माण किए भुगतान हुआ है तो नियमानुसार वसूली निकालकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

योजनाओं के नाम तक नहीं बता पाए बीडीओ, सीईओ चौधरी की मॉनिटरिंग पर उठे सवाल

पंचायतराज मंत्री रमेश मीणा ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक

झुंझुनूं, (निसं)। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्री रमेश मीणा इन दिनों पूरे एक्शन में हैं और अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। ऐसी ही क्लास उन्होंने झुंझुनूं में भी लगाई। दरअसल करीब पांच घंटे तक उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें मीणा ने कुछ बीडीओ को योजनाओं के पूरे नाम पूछे तो उन्हें योजनाओं के पूरे नाम तक पता नहीं था। जिस पर मीणा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप पढ़े-लिखे लोग हैं।

आपको बाबू के आंकड़ों के आधार पर पारंपरिक तरीके से कार्य करने की जगह विभाग की गाइडलाइन व बुक का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मीणा ने जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सीईओ की सही मॉनिटरिंग और लापरवाही के कारण जिले में ऐसे हालात हो रहे हैं। जो सही नहीं है। विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी सही जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश है कि नई गाइडलाइन से आमजन को फायदा मिल सके। विकास अधिकारी बाबूओं



पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

द्वारा दिए गए आंकड़े व पारंपरिक कार्य शैली के आधार पर बैठे-बैठे साइन करने काम कर रहे हैं।

मंत्री मीणा ने मनरेगा योजना के कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को नियमित रूप से नरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने व महिला मेट बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार व

खेतड़ी विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, जल टाहण एवं भू संरक्षण के निदेशक रश्मि गुप्ता, नवलगढ प्रधान दिनेश सुंडा, झुंझुनूं प्रभार पुष्पा चाहर, बुहाना प्रभार हरिकिशन यादव, अलसीसर प्रभार घासीराम पुनिया, जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी, एडीएम जेपी गौड़, एसीईओ रामनिवास, उपवन संरक्षक राजेंद्र हुडा, पीडब्लूडी के

एसई शंकरलाल आदि मौजूद थे।
दूसरी जगह भेजने और नोटिस की चेतावनी :- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं से जुड़े सवाल, धरातल पर किए जा रहे कार्यों व विभिन्न योजनाओं के तहत रुपए खर्च नहीं करने से नाराज शासन सचिव नवीन जैन ने उदयपुरवाटी के बीडीओ

चैक अनादरण के आरोपी को सजा

भीलवाड़ा, (निसं)। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-1) भीलवाड़ा ने चैक अनादरण के आरोपी/अभियुक्त को एक प्रकरण में 1 वर्ष के कारावास तथा 9,00,000/- रूपयें के प्रतिकर से दण्डित किया।

परिवारी लक्ष्मणलाल आत्मज इंंदरमल सिंघवी निवासी भीलवाड़ा ने अधिवक्ता ललित सांखला के मार्फत एक परिवार न्यायावय में अभियुक्त बाबूलाल आत्मज घननदेव आचार्य, निवासी ईरास, भीलवाड़ा के विरुद्ध 4,50,000/- के चैक अनादरण बाबत प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय ने आरोपी/ अभियुक्त बाबूलाल को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत चैक अनादरण के अपराध का दोषी मानते हुए प्रकरण में 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में रिमांड बढ़ाया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर-असारवा (अहमदाबाद) रेलमार्ग पर उदयपुर से 35 किमी खारवा-चांदा रेलवे ट्रैक की ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट के आरोपियों की कोर्ट ने रिमांड अवधि पांच दिन और बढ़ा दी है। वहीं अवैध विस्फोटक बेचने वाली को रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया।

ओड़ा रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट मामले में आरोपियों धूलचंद और प्रकाश मीणा की रिमांड अवधि बुधवार को पूरी होने पर एटीएस, उदयपुर यूनिट के एएसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में कोर्ट में पेश किया। जहां पुलिस ने अनुसंधान में और भी

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत

बीकानेर, (कासं)। लूणकरनसर में ईंट भट्टों पर काम करने वाले तीन मजदूर बाइक पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर चारे से भरी दो पिकअप खड़ी थी। इसी कारण सामने से आ रहा ट्रक नजर नहीं आया। लूणकरनसर के चक 264 के पास हरियासर गांव में ईंट का भट्टा है। इसी भट्टे पर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा निवासी तीन दोस्त काम करते हैं। बुधवार को अमावस्या के कारण अवकाश था। ऐसे में तीनों दोस्त लूणकरनसर घर का सामान लेने गए थे। वापसी के दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। बाइक पर सवार राजू पुत्र बृजलाल नायक, मदन लाल पुत्र चौधराम मेघवाल और श्योपत पुत्र बृजलाल नायक की मौके पर ही मौत हो गई। राजू और श्योपत सगे भाई थे। इन तीनों के ऊपर से ट्रैक्टर निकल गया। ऐसे में तीनों दूर-दूर सड़क पर गिरे मिले। आसपास के लोग अस्पताल भी लेकर गए लेकिन तीनों मृत थे। अब तीनों की बाँड़ी लूणकरनसर अस्पताल में रखी गई है, जहां तीनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मौके पर दो पिकअप गाड़ियां खड़ी थी। इसी कारण ट्रैक्टर और बाइक सवार दोनों को कोई भी नजर नहीं आया।

सहायक निदेशक (पॉलीग्राफ डिबीजन), लेक्चरर अगद तंत्र विचारित सूची जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह (ग्रुप-1) विभाग में सहायक निदेशक (पॉलीग्राफ डिबीजन) एवं आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में अगद तंत्र विषय के लेक्चरर पदों हेतु पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की गई है। साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग द्वारा सहायक निदेशक (पॉलीग्राफ डिबीजन) पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए संवीक्षा परीक्षा-

युवक की मूंछे और बाल काटे, वीडियो वायरल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के निकटवर्ती खारडा भांडू में युवक की मूंछे और बाल काटने जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीडित युवक ने हालांकि अभी तक पुलिस के पास में उपस्थित होकर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मगर युवक जिस घर में परिचित से मिलने गया उसके पड़ौसियों को मिलना नागवार लगा और बाल मूंछे काट डाले।

पुलिस ने फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। एक महिला ने अपने पड़ौसियों के खिलाफ लज्जा भंग की रिपोर्ट दी है। बोरानाडा थानाधिकारी किशनलाल ने सूची कि खारडा भांडू की रहने वाली एक महिला ने अपने

पड़ौस के चार लोगों कुने खां, हाकम खां, शाहरूक खां एवं कालू खां के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं लज्जा भंग की रिपोर्ट दी है। घटना 20 नवंबर की है। थानाधिकारी किशनलाल ने बताया कि जिस महिला की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई उसके घर में जीतू नाम का एक शख्स आया हुआ था। जो कि उनके मिलने वाला है। जीतू के घर में आने की जानकारी मिली तो पड़ौसियों को उसका वहां आना नागवार लगा। पड़ौसियों ने उसे पकड़ कर बाल और मूंछे काट दी गईं। यह घटना भी 20 नवंबर को ही हुई थी। बाल मूंछे काटे जाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी सकते में आ गई।

आरोपी पकड़ा

करोली, (निसं)। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री देखने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में करौली कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। करौली थाना अधिकारी डॉ. उदय भान ने बताया कि बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री देखने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर साइबर सेल एनसीआरबी दिल्ली पूरे देश में विशेष निगरानी कर रही। सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पकड़ में आया। जिस पर एनसीआरबी साइबर टिप लाइन दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एसपी नारायण टोगस ने युवक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने रुपेश सिंहल 20 निवासी सत्यवती विहार कॉलोनी करौली को गिरफ्तार किया है।

पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने का जुनून

नागौर से पप्पू चौधरी ने शुरू की साइकिल यात्रा, झुंझुनूं पहुंचा

झुंझुनूं, (निसं)। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए माउंट एवरेस्ट तक साइकिल यात्रा पर निकले पप्पू चौधरी झुंझुनूं पहुंचे। यहां पहुंचने पर युवाओं ने पप्पू का स्वागत किया और उनके हौसले को सराहना करते हुए कहा कि अगर हर व्यक्ति में पप्पू चौधरी जैसी सोच पैदा हो जाए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पप्पू ने 1 सितंबर को नागौर से साइकिल यात्रा की शुरू की थी। अब तक राजस्थान के 11 जिलों की साइकिल पर यात्रा कर चुके हैं। पप्पू चौधरी नागौर से होते हुए जोधपुर, पाली, सिराही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के बाद झुंझुनूं पहुंचे। वह अब तक चार हजार किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए लगभग डेढ़ साल तक यात्रा करेंगे। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए बीस हजार किलोमीटर से ज्यादा की



पर्यावर संरक्षण की अलख जगाने के लिए पप्पू चौधरी झुंझुनूं पहुंचे।

दूरी तय करेंगे। पप्पू के इस काम हर जगह सराहना हो रही है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है।

पप्पू चौधरी नागौर जिले के खींवसर के रहने वाले हैं। उनका सपना है कि माउंट एवरेस्ट कैप तक साइकिल यात्रा निकालकर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण हासिल कर एवरेस्ट अभियान

दल का हिस्सा बने। पप्पू को राजस्थान में तीन महीने और लगेंगे उसके बाद साल भर तक यात्रा कर माउंट एवरेस्ट बेस कैप तक पहुंचेंगे। पप्पू बताते हैं कि उन्होंने पर्यावरण बचाने का जुनून है और इसके लिए वे काम कर रहे हैं, ताकि लोग उन्हें देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे।

रोडवेज कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे चक्का जाम

बीएमएस ने किया आंदोलन से किनारा, बसों के संचालन के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन



मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संगठन काफी दिनों से आंदोलन कर रहा है।

खेतड़ी, (निसं)। रोडवेज कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो गुरुवार से रोडवेज का चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन से किनारा करते हुए आंदोलन में शामिल नहीं होकर रोडवेज के संचालन को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन एटक के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की ओर से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ अभियान के तहत 21 सूत्री मांगों को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पिछले दो दिन से

खेतड़ी, आगार परिसर में धरना भी दिया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार व निगम प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं। वहीं परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला के साथ सचिवालय में बैठक कर समस्याओं का समाधान करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से कर्मचारियों में आक्रोश है। जिसके चलते चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन से अलग होते हुए रोडवेज बसों के संचालन को लेकर सुरक्षा मुद्देया करवाने की मांग की है। संघ के तहसील संयोजक शीशराम गुर्जर ने बताया कि संयुक्त मोर्चा द्वारा

प्रस्तावित हड़ताल का भारतीय मजदूर संघ समर्थन नहीं करता है। वैवाहिक सीजन होने के कारण निगम के वाहनों पर यात्री भार का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा निगम को राजस्व की हानि भी उठानी पड़ेगी। इसी को लेकर भारतीय मजदूर संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा तथा बसों का संचालन प्रभावी रूप से किया जाएगा। इस दौरान होने वाली किसी प्रकार की अग्रिय घटना को देखते हुए सुरक्षा मुद्देया करवाने की मांग की है तथा डिपो मैनेजर व एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रोडवेज बसों का नियमित संचालन करवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर दोनों पक्षों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।

बिजली विभाग ने नगरपालिका के करीब 110 कनेक्शन काटे

■ बिजली विभाग के करीब 80 लाख रुपए बकाया

कच्ची बस्ती होने के कारण यहां गरीब तबके के लोग निवासरत हैं जिनके घरों में पानी का कनेक्शन नहीं होने के चलते नगरपालिका प्रशासन की ओर से करीब 10 हैण्डपम्पों को हटाकर वहां इलेक्ट्रिक मोटर स्थापित कर बिजली कनेक्शन काटने के कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में ईंओ का पद खाली होने के चलते किसी ईंओ का चार्ज असमंजस स्थिति में है। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 व 2 जाखानगर में पालिका की करीब 10 टंकिया लगाई गई थी। उक्त क्षेत्र

नगरपालिका सुमेरपुर की अध्यक्ष उषा कंवर ने बताया कि वर्तमान में पालिका में फण्ड नहीं है, राज्य सरकार ने चुंगी नाका मद का करीब एक करोड़ नहीं उपलब्ध कराया है। मैंने बिजली विभाग के एसई से निवेदन किया है कि जल्द ही बकाया भुगतान आपको कर देंगे। शाम तक दोबारा कनेक्शन हो जाएंगे। डिस्कॉम सुमेरपुर के एईएन अशोक कुमार मीणा ने बताया कि नगर पालिका के करीब 80 लाख बकाया होने चलते उच्चाधिकारियों से सहमति लेकर कार्रवाई की गई है।



पुष्कर के पंडित गोताखोर राहुल पाराशर ने बताया की बाबाजी मोहन गिरी के सानिध्य में रूस की रहने वाली दो विदेशी महिलाओं ने अपने पूर्वजों के पिंडदान किये। रिना व कातिया ने पुष्कर सरोवर की पूजा करके बहुत ही शान्ति महसूस की। इसके बाद दोनों महिलाओं ने सर्दी से बचाव के लिए सौ कम्बल सड़क पर सोने वाले बाबा, साधुओं को वितरित किये।

महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने केन्द्र सरकार पर लगाए आरोप

प्रदेश में 5 हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की नहीं दे रहा केंद्र मंजूरी, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहा



मंत्री ममता भूपेश

लेकिन केंद्र सरकार बड़े हुए मानदेय के आधार पर अपना हिस्सा नहीं दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतिगत निर्धारण है कि मानदेय का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र तथा 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी। लेकिन बिड़बना है कि हम 70 फीसदी पैसा दे रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार 30 फीसदी राशि भी समय

पर नहीं दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है। नीतिगत समझौतों पर काम नहीं कर रहा है। बावजूद इसके भाजपा के सांसद केंद्र में कुछ बोलते नहीं। **ईआरसीपी और मानगढ़ पर बरसी ममता :-** मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार को केवल अपने विभागीय कार्यों में सौतेले व्यवहार को लेकर ही नहीं घेरा। बल्कि उन्होंने कहा कि ईआरसीपी और मानगढ़ का क्रेडिट गहलोत सरकार ना ले जाए। इसके कारण ना तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा रहा है और ना ही मानगढ को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार को एक अभिभावक की तरह सभी राज्यों को देखना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज गहलोत सरकार ना मिल जाए। इसलिए ना तो ईआरसीपी और ना ही मानगढ़ पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। जबकि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ईआरसीपी और मानगढ़, दोनों में जो भी

खर्चा आएगा। राज्य सरकार खर्च करेगी। फिर भी केंद्र सरकार पॉलिटिकल माइलेज को जमाने को ना मिले। इसलिए ना केवल चुप है। बल्कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजस्थान के होते हुए भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। **भाजपा की नौटंकी है जनाक्रोश रैली, प्सॉप शो साबित होगी :-** भाजपा की जनाक्रोश रैली को लेकर ममता भूपेश ने कहा कि चार साल में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका को तो नहीं निभाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए चुनावी स्टंट के लिए भाजपा जनाक्रोश रैली की नौटंकी कर रही है। जो एक पलाय शो साबित होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में पहली बार कोई नेता पौने 4 हजार किलोमीटर की यात्रा जाए। इसलिए ना तो ईआरसीपी और ना ही मानगढ़ पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। जबकि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ईआरसीपी और मानगढ़, दोनों में जो भी



आगामी विधानसभा चुनावों के महीनजर भाजपा प्रदेश भर की 200 विधानसभा सीटों पर जनक्रोश यात्रा करने जा रही हैं, जिसकी तैयारी के सम्बंध में जयपुर में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को संबोधित किया।

भाजपा की 200 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर जयपुर में हुई कार्यशाला

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, आपको भरोसा देता हूँ कि 2023 और 2023 के बाद अनंतकाल तक भाजपा राजस्थान में सत्ता का माध्यम बनेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज करेगी और इसलिए यह संघर्ष कांग्रेस के जंगलराज के खिलाफ आपातकाल जैसा ही है

जयपुर, 23 नवम्बर (का.सं.)। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की भाजपा जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर सी स्वीम स्थित महावीर स्कूल सभागार में जिला व विधानसभा संयोजक व सह संयोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया।

जन आक्रोश यात्रा कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन में जनविरोधी नीतियों व वादाखिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई नौजवान केवल 35 सी रूपये कर्जे के कारण ना केवल अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, बल्कि उसका पूरा परिवार अपने प्राणों को त्यागने को मजबूर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं होगा कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर का सोहनलाल कडेल अपना लाइव वीडियो बनाकर यह कहा कि “मैं अपनी मौत को इसलिए गले लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कर्जे से चंग आकर आत्मदाह कर रहा हूँ, जिस प्रदेश के मुखिया को किसी अबला के 35 टुकड़े किए जाने पर सामान्य घटना लगती है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का 1 वर्ष का आंकड़ा 6337 हो, प्रतिदिन औसत 17 बलात्कार, 7 हत्या, जिसके खते में दर्ज हो, चार वर्षों में सवा 8 लाख से अधिक मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज होते हों, आपके घर नवजात पैदा होता होगा आप लोग खुशियां मनाते होंगे, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में जब कर्जे का आंकड़ा 5 लाख करोड़ के लगभग पहुंचता है तो वह बेटा-बेटी 80 हजार का कर्जा लेकर पैदा होता होगा।

बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच सकें।

- कार्यशाला में प्रदेशभर से 500 से अधिक जिला व विधानसभा संयोजक एवं सह संयोजक जुटे।**
- राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा और कमल के फूल के छाते के नीचे आपकी पहचान, आपका स्वभिमान, आपका गौरव, आपकी खूबी, आपका वर्चमान, आपका भविष्य यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मिशन 2023 के विजय संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध होकर जुट जाएं।**

उन्होंने कहा कि कोरोना त्रासदी के 2 साल बहुत ही मुश्किल से निकले, लेकिन इस दौरान भाजपा के 685 कार्यकर्ताओं ने सेवा करते करते अपने प्राणों का उर्सगं कर दिया।

पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में 30 प्रतिशत से ज्यादा है, 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी थी, 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कहते घूम रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 69 लाख का क्या होगा यह रोडमैप राज्य सरकार के पास नहीं है। हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार की रफ्तार है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर जब पहला कदम रखेंगे, मेरा पहला सवाल होगा किसान कर्जमाफी के वादे को लेकर। पता नहीं वर्ष 2018 की जनसभा में किसने राहुल गांधी को पर्ची पहुंचाई और जब वो कह रहे थे कि 1 से 10 तक गिनती गिनुंगा किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, राजस्थान के 60 लाख किसान 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्जों की माफी का आज भी इंतजार करते हैं।

पूनिया ने कहा कि “मुझे पता लगा कि राहुल की मालाखेड़ा में सभा है, अलवर के मालाखेड़ा में बड़ा रोचक वाक्या हुआ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई तो तुरंत नौकरी, एक नौजवान को खड़ा किया और पूछा

आपका क्या नाम है उसने कहा कि, रूपसिंह, रूपसिंह की नौकरी पक्की। अब 4 साल हो गए रूपसिंह बेचारा चक्कर काटते ही घूम रहा है। इसलिए यह राजस्थान की धरती पर राहुल गांधी कदम रखें तो इन बातों का जवाब जरूर लेकर आएंग।”

उन्होंने कहा कि“मित्रों आपमें से बहुत लोगों ने वर्ष 1975 की इमरजेंसी को सुना होगा और यहां कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी को देखा व भुगता भी है। आज राजस्थान का वही दृश्य है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपसे न्याय मांगती है, हम लोग राजस्थान की जनता के लिए, उसके लोक कल्याण के लिए केवल सत्ता के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए संकल्पित है, राजस्थान का राजनीति के अज्ञातशत्रु स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत की जन्म शताब्दी है, उनकी सरकार से लेकर भाजपा सरकारों में हुए अबतक के विकास कार्यों से राजस्थान की दिशा को दशा को बदलने का काम किया, पिछले दिनों रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आए, उन्होंने बताया कि अकेले राजस्थान में 56 हजार करोड़ रूपए रेल नैटवर्क को विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने दिए।

पूनिया ने कहा कि “मुझे पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाने का मौका मिला, मैंने एक लाइव वीडियो जारी किया था, जोधपुर के नजदीक काहीं किसी शोक सभा में गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लगना आधा घंटा लगना जाकर आ

जाओगे। सफर 30 किलोमीटर था और मुझे एक घंटा लगा, पता नहीं लग रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्डे में सड़क, इतने खड्डे थे जितने कांग्रेस पार्टी के शासन में और कांग्रेस पार्टी में हैं, बिजली और पानी की दशा आपको पता है, पानी का हाहाकार आपको पता है, अस्पताल और स्कूलों की दशा आपको पता है।”

“अशोक गहलोत ने खोल दिए खूब सारे कॉलेज खोलें, लेकिन ना बििल्डिंग है, ना फैकल्टी है, स्कूल खोल दिए संसाधन नहीं है। इसलिए ऐसी अराजक, आतलापी सरकार के खिलाफ यह दृश्य वैसा ही है जैसा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ, जो गुजरात से शुरू हुआ और बिहार से समग्र क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ।”

उन्होंने कहा कि“यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कौसे सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल कर दूध सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।”

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, हेमराज मीणा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह खींवसर, सुरेन्द्र पाल सिंह टोटी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, महेंद्र जाटव, मधु कुमावत इत्यादि भी उपस्थित रहे।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी तीखी टिप्पणी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
दिये गये सिद्धांतों को लागू करने वाले आवश्यक नियम तैयार नहीं किये हैं, जबकि केन्द्र तथा राज्यों ने विद्युत-क्षेत्रों के नियमन के लिये नीतियाँ तथा गाइडलाइनें तैयार कर दी हैं।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. धर्नजयवाई. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपना एवं जे.बी. पाटीवाला की बैंच ने कहा कि जहाँ-जहाँ आयोगों ने नियम तैयार कर दिये हैं, उनमें संशोधन किये जायेंगे ताकि उनमें शुल्क-निर्धारण की रीति-नीति के चयन के लिये मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये जा सकें।
बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच सकें।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुनवाई के लिये गये इस बहुत बड़े मुद्दे के तुरन्त बाद यह बात कही।
भूषण ने कहा, “अरूण गोयल अभी गुरवार तक सरकार में सचिव-स्तर के ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। एकाएक शुक्रवार को उन्हें वी.आर.एस. दे दिया गया तथा चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया।”
उन्होंने कहा कि वे 60 वर्ष की उम्र पूरा करने पर 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने को थे।

अदालत ने सरकार के वकील, अटॉर्नी जनरल आर. वैक्टरमानी की इस आपत्तियों को खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत उदाहरण लेना अच्छी बात नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील से कहा, “हम यह देखना चाहते हैं कि यह मैकिनज्म क्या है। हम इसे प्रतिकूल अर्थ में नहीं लेंगे तथा इसे अपने रिर्काई के

लिये रखेंगे, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, जैसा कि आपका दावा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके पास कल तक का समय है।”

आयोग की वेबसाइट के अनुसार, अरूण गोयल ने इसी सोमवार को, 21 नवम्बर को ही पदभार ग्रहण किया है। पंजाब कैडर से 1985 के बैंच के आई.ए.एस. ऑफिसर रहे गोयल, 37 साल से अधिक अवधि तक सेवाएँ देने के बाद, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुये हैं।

फरवरी 2025 में राजीव कुमार द्वारा पद त्याग किये जाने के बाद, गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में होंगे।

इससे पहले, अदालत ने कहा कि “संविधान की खामोशी” का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

कार्यकाल पूरा नहीं किया।

अदालत ने कहा कि एक के बाद एक, सरकारों ने ई.सी.आई. की स्वतंत्रता “पूरी तरह नष्ट कर दी” है तथा किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त 1996 के बाद आयोग के प्रमुख के रूप में, अपना छ: वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया।

अदालत ने कहा, “यह बहुत ज्यादा व्याकुल कर देने वाली प्रवृत्ति है। टी.एन. शेणन (जो 1990 से 1996 तक छ: साल सी.ई.सी. रहे थे) के बाद, यह पतन शुरू हो गया तथा किसी भी व्यक्ति को पूरा कार्यकाल नहीं दिया गया। सरकार यह कर रही है कि चौँकि उसे जन्मतिथि ज्ञात होती है, इसलिए वह सुनिश्चित कर लेती है कि सी.ई.सी. नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरे छ: साल का कार्यकाल नहीं मिल सके।” अदालत ने कहा कि “चाहे यू.पी.ए. सरकार रही हो या यह

‘माही सागर बांध का पानी जालोर, बाड़मेर व सिरोही आयेगा’

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि, जनवरी 2023 तक, इस पानी को राजस्थान लाने के लिए विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश करे

जालोर, 23 नवम्बर (कासं)। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार ब्रदीदान ने बताया कि संघर्ष समिति की ओर से मैंने गुजरात के विभागों में 446 बार आरटीआई लगाकर सूचनाएँ माँगी। उन दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकार को जनवरी के दूसरे सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह किसानों की पहली जीत है, हम प्रयास करेंगे कि सरकार इस सत्र में माही परियोजना के लिए बजट जारी करे।

ब्रदीदान ने कहा जालोर समेत बाड़मेर और सिरोहीवासियों के लिए खुशखबरी है। पिछले लंबे समय से माही बजाज सागर परियोजना को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे प्रयासों को कुछ हद तक राहत मिली है। दरअसल, समिति की ओर से माही बांध के पानी को जालोर, सिरोही व बाड़मेर को उपलब्ध करवाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मार्च 2021 में एक जनहित याचिका दायर की थी, उसमें अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक एक प्लान बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को जालोर में प्रैसवार्ता के दौरान कहा, राज्य सरकार को किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए गए चार सुझावों के साथ-साथ खुद का विकल्प भी शामिल करने को निर्देश दिया हैं।

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि अब न्यायालय का सहयोग मिलने से भरोसा बढ़ गया है, इसके कार्य की योजना को लेकर समिति की ओर से 28 नवम्बर को नरपुरा में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, ताकि सरकार माही बजाज योजना के लिए इस बजट सत्र में बजट जारी कर सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का माही बांध एवं गुजरात में बने कड़ाणा बांध के पानी के वितरण का समझौता हुआ था। जिसमें प्रथम व पंचम बिंदु में साफ लिखा है कि माही व कड़ाणा बांध के पानी पर पश्चिमी राजस्थान का हक है। इस समझौते पर राजस्थान के तत्कालीन कृषि मंत्री नाथुराम मिर्वा, गुजरात के जल संसाधन सचिव एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री विजय त्रिवेदी के हस्ताक्षर

‘मोटर यान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 में संघ के पत्र पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए थे,लेकिन छह साल बाद भी सिर्फ स्टेनोग्राफर और लेखाधिकारी ही नियुक्त किए गए, लेकिन सभी जगहों पे पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेशों से श्रम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को भी मोटर वाहन के लम्बित दावे हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर लेखाधिकारी और स्टेनोग्राफर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे अधिकरण का काम ठीक से नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्देशों में सिर्फ स्टेनोग्राफर और लेखाधिकारी के पद ही भरने का कहा था, जो अधिकांश जगह भर दिए गए हैं। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोरणा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दो सप्ताह में तालिका और शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और इनकी संख्या कितनी है। राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताएं कि रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा।

ई.डब्ल्यु.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

“निष्प्रभावी करने” के लिये आधारभूत सैद्धांतिक ढाँचे का प्रयोग “तत्त्ववाद” के रूप में करने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। बैंच ने 3:2 के बहुमत 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला दिया था।

सरकार, रीति-नीति यही रही है।”
बैंच ने कहा, “यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों में छ: सी.ई.सी. रहे तथा मौजूदा एन.डी.ए. सरकार के करीब आठ वर्षों में आठ सी.ई.सी. रह चुके हैं। जहाँ तक अपने पद का संबंध है, यह तीर-तरीका चिन्तित कर देने वाला है। संविधान में इस बाबत कोई “चैक्स एवं बैलेन्सेज” नहीं है। इस तरह से संविधान की खामोशी का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। चौँकि को कोई कानून ही नहीं है, अतः कानूनी रूप से वे (सरकारें) सही हैं। कानून के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता।”

बैंच ने अटॉर्नी जनरल आर. वैक्टरमानी से कहा, “2004 के बाद सी.ई.सी. की सूची देखें, उनमें से अधिकांश का कार्यकाल दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहा। कानून के अनुसार, सी.ई.सी. का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो भी पहले हो, तक रहना

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सफलता नहीं मिल रही। लेकिन अगर पार्टी बिहार के मौजूदा महागठबंधन, जो जे.डी.यू., आर.जे.डी. तथा कांग्रेस से मिलकर बना है, के साथ अपने चुनाव-पूर्व गठबंधन को औपचारिक रूप दे देती है तो पार्टी की संभावनाएं कुछ बेहतर हो सकती हैं। शिव सेना की साथ लेकर, महागठबंधन के नेता ऐसा मान सकते हैं कि शिव सेना उनके लिये वैसी सिद्ध हो सकती है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने को तैयार करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.टी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मीटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, “वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।” आदित्य ठाकरे ने कहा, “हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मीटिंग नहीं हो सकी। हमारे कई बिन्दुओं व जन चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।”

उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, सी.ई.सी. तथा ई.सी. के नियुक्ति के लिये कोलौजियम जैसी किसी व्यवस्था की माँग की गई है।
सी.ई.सी. की नियुक्ति के वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हुये, केन्द्र सरकार ने दलील दी कि अदालत इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया ठीक तरह से संचालित हुई है। पिछले सप्ताह, केन्द्र ने इसका जबरदस्त विरोध किया था तथा कहा था कि ऐसी कोई भी कोशिश संविधान को संशोधित करने के बराबर होगी।

इस बिन्दु पर अदालत ने कहा: “इसका कारण सत्तारूढ़ पार्टी को दुराग्रही प्रकृति तथा जिद ही है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन वह वर्तमान स्थिति को समाप्त करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इस स्थिति में सरकार कुछ भी करने के लिये स्वतंत्र होती है, यह

जिसकी अनुमानित लागत 6500 करोड़ तय की गई। परंतुरिपोर्ट आने तक सरकार बदल गई और 2008 से 2013 तक यह फिर से जालोर सिरोही बाडमेर की महत्वपूर्ण भागीरथी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब राजस्थान किसान संघर्ष समिति को पिछले 14 साल का संघर्ष अब रंग लाने लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से राज्य सरकार को इन सुझावों पर योजना बनाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं ताकि माही बांध का पानी बाड़मेर जालोर के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए

भारतीय किसान संघ समिति के संयोजक विक्रमसिंह पुनासा ने बताया कि आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालय में रिट पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने तो यह कह दिया कि हमें इस सम्बंध में जानकारी तक नहीं है। राज्य सरकार ने कुछ सहयोग जरूर किया क्योंकि, इस पानी की जालोरी व बाड़मेर को जरूरत है। अब हाईकोर्ट के निर्देश से हमें कुछ हौसला मिला है। उम्मीद है सरकार भी योजना बनाकर बजट जारी करेगी।

महाराष्ट्र का एम.बी.ए...

बिहार के मुख्यमंत्री तथा उनके उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित, अन्य राज्यों में गैर-भाजपा गठबंधन सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगे हुये हैं तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित, बहुत विपक्षी नेताओं के मन टटोले हैं। नीतीश कुमार ने तो अधिकृत वक्तव्य के रूप में कह भी दिया है कि अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधन भाजपा को हरा सकते हैं। शिव सेना यू.बी.टी. का विपक्षी गठबंधन में शामिल होना सैद्धांतिक रूप से विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। लेकिन जे.डी.यू. नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के समायोजन से विपक्षी नेताओं का यह दृढ़ निश्चय बेहतर तरीके से सम्प्रतिष्ठ हो सकता है कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से लड़ने के कलये उद्यत है।

भारत जोड़ो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आकर बताया चाहिए कि आखिर इस पूरे षडयंत्र के पीछे कौन-कौन लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि “मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड्गें जी से मिलकर आया हूँ और मेरी उनसे वन टू वन बात हुई है और जल्द ही इस बातचीत का नतीजा निकलेगा।”

बैंच ने चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा, “अब प्रश्न यह उठता है कि जब चुनावों के शुद्धता तथा निष्पक्षता, लोकतंत्र के साथ गुंथी हुई हों तो क्या अदालत को खामोश रहना चाहिए।

‘फुटबॉल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया है जिसमें कोर्ट ने 18 मई और 3 अगस्त के आदेश को बदलने की मांग की गई थी ताकि फीफा निलम्बन को वापस ले ले और भारत को अण्डर-17 वीमैनस वर्ल्ड कप फुटबॉल के आयोजन का अधिकार मिले। देश में पहली बार 11-30 अक्टूबर को फीफा इवेंट आयोजन किया गया।